डाक पंजीकरण संख्या बी.एस.टी.६२ आर.एन.आई.संख्या ४०३६७/८४ नेट संस्करण www awajdarpan.com पर पढें

साप्ताहिक

आवाज दर्पण

प्रत्येक रविवार

बस्ती (उ.प्र.) वर्ष ४९ अंक ३० रविवार १४ जुलाई से २० जुलाई २०२४ मूल्य तीन-रुपये

अयोध्या के बाद बद्रीनाथ भी हारी भाजपा

13 में से 10 पर इण्डिया गठबधन की जीत

नई दिल्ली (आभा)। लोकसभा चुनाव में अयोध्या हारने के बाद भाजपा को एक और धर्मनगरी में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। विधानसभा उपचुनावों में उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट पर उसे मुंह की खानी पड़ी है। बद्रीनाथ चार धाम में आता है औ यहां बड़े पैमाने पर विकास कार्य चल रहे हैं। इसके बावजूद मिली हार भाजपा के लिए परेशानी बढ़ाने वाली है। गौरतलब है कि हालिया लोकसभा चुनाव में भाजपा को अयोध्या में हार का सामना करना पड़ा था। भगवान राम की जन्मस्थली पर भाजपा की हार के बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इसके अलावा अयोध्या से सटे बस्ती के साथ राम वन गमन पथ पर आने वाले प्रयागराज, चित्रकूट, नासिक और रामेश्वरम की सीटें भी उसे गंवानी पड़ी थीं। अब कुछ ऐसा ही हाल बद्रीनाथ में हुआ है। इसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या भाजपा सरकार धार्मिक स्थलों का विकास करने के बावजूद स्थानीय वोटरों को लुभाने में विफल हो रही है? बता दें कि बद्रीनाथ सीट पहले भी कांग्रेस के ही पास थी। लेकिन कांग्रेस विधायक रहे राजेंद्र भंडारी लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में चले गए थे। इसके चलते इस सीट पर उपचुनाव की नौबत आई थी।

उप चुनाव में 13 में से 10 सीटों पर इंडिया के उम्मीदवार जीते हैं। हिमाचल और मध्य प्रदेश एक-एक सीट पर भाजपा और बिहार में एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। चुनाव आयोग ने सभी 13 सीटों के नतीजे आधि ाकारिक रूप से घोषित कर दिए हैं। इनमें पंजाब में जालंधर पश्चिम सीट पर आप के मोहिंदर भगत जीत गए हैं। हिमाचल की देहरा सीट से कांग्रेस की कमलेश ठाकुर, नालागढ़ से कांग्रेस के हरदीप सिंह बावा और हमीरपुर से भाजपा के आशीष शर्मा को जीत मिली है। पश्चिम बंगाल में सभी सीटें टीएमसी के खाते में जाती नजर आ रही हैं। यहां रायगंज में कृष्णा कल्याणी, बागदा में मधुपर्णा ठाकुर, रानाघाट दक्षिण में मुकुट मणि अधिकारी और मानिकतला में सुप्ति पांडे को जीत मिली है। मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा सीट पर भाजपा के कमलेश प्रताप शाह की जीत हुई है। उत्तराखंड में बदरीनाथ सीट पर कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला और मंगलौर सीट पर कांग्रेस के काजी मोहम्मद निजामुद्दीन जीते हैं। बिहार में रुपौली सीट पर लोजपा (रामविलास) से बागी होकर चुनाव लड़े शंकर सिंह जीत गए हैं। तमिलनाडु में विक्रवंडी विधानसभा सीट पर डीएमके के अन्नियुर शिवा को जीत मिली है।

25 जून संविधान हत्या दिवस घोषित

नई दिल्ली (आभा)। केंद्र सरकार ने 25 जून को हर साल 'संविध ाान हत्या दिवस' के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। इसे लेकर केंद्र सरकार की ओर से शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसमें कहा गया, 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी। इसके बाद उस समय की सरकार की ओर से सत्ता का घोर दुरुपयोग किया गया और भारत के लोगों पर ज्यादतियां और अत्याचार किए गए। जबकि, भारत के लोगों को भारत के संविधान और भारत के मजबूत लोकतंत्र पर दृढ़ विश्वास है। इसलिए, भारत सरकार ने आपातकाल की अवधि के दौरान सत्ता के घोर दुरुपयोग का सामना और संघर्ष करने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' घोषित किया है। भारत के लोगों को भविष्य में किसी भी तरह से सत्ता के घोर दुरुपयोग का समर्थन नहीं करने के लिए फिर से प्रतिबद्ध किया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके कहा, '25 जून 1975 को तत्कालीन प्रध ाानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंट दिया था। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय किया है। यह दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगा, जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था।'

अमित शाह ने अपनी पोस्ट में आगे कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की ओर से लिए गए इस निर्णय का उद्देश्य उन लाखों लोगों के संघर्ष का सम्मान करना है, जिन्होंने तानाशाही सरकार की असंख्य यातनाओं व उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए संघर्ष किया। 'संविधान हत्या दिवस' हर भारतीय के अंदर लोकतंत्र की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अमर ज्योति को जीवित रखने का काम करेगा, ताकि कांग्रेस जैसी कोई भी तानाशाही मानसिकता भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न कर पाए।'

दूसरी ओर, कांग्रेस ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करके कहा, 'नॉन-बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री एक बार फिर हिपोक्रेसी से भरा एक हेडलाइन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भारत के लोगों से 4 जून, 2024 (जिसे इतिहास में मोदी मुक्ति दिवस के नाम से जाना जाएगा) को मिली निर्णायक व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक हार से पहले उन्होंने 10 सालों तक अघोषित आपातकाल लगा रखा था। यह वही नॉन-बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत के संविधान और उसके सिद्धांतों, मूल्यों व संस्थानों पर सुनियोजित ढंग से हमला किया है।

भाजपा ने शुरू किया मतदाता अभिनन्दन समारोह

संवाददाता-बस्ती। लोकसभा चुनाव परिणाम एवं तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए जाने के बाद भाजपा ने विधानसभा स्तरीय मतदाता अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। समारोह के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। भाजपा नेता अमृत कुमार वर्मा ने बताया की बस्ती लोकसभा चुनाव में भाजपा को सफलता नही मिली इसके बावजूद भी भाजपा अपने वोटरों को सहेजने में कोई कसर नही छोड़ना चाहती। बस्ती लोकसभा चुनाव में भाजपा को कुल लगभग 4 लाख 26 हजार वोट मिले। इन वोटरों का सम्मान करने के लिए भाजपा विधानसभा वार मतदाता अभिनन्दन समारोह का आयोजन कर रही है। दो दिवस में प्रस्तावित यह कार्यक्रम 12 जुलाई को विधानसभा रुध ाौली के सल्टौआ ब्लाक सभागार में, कप्तानगंज में बभनान बाजार, हर्रैया में ब्लाक सभागार में संपन्न हुआ, 13 जुलाई को बस्ती सदर में अटल बिहारी प्रेक्षागृह बस्ती और महादेवा विधानसभा के शिक्षा शक्ति मैरेज हाल कुदरहा में होना है। भाजपा कार्यकर्ताओं और मतदाताओं का लोकसभा चुनाव में दिए गए योगदान को लेकर आभार व्यक्त किया। वरिष्ठ व प्रबुद्ध मतदाताओं को निवर्तमान सांसद हरीश द्विवेदी और जिलाध्यक्ष विवेकानन्द मिश्र ने भगवा अंगवस्त्र पहना कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में क्रमवार हजारो मतदाता सम्मानित हुए।

निवर्तमान सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि भारत लोकतांत्रिक देश है। यहां मतदाता ही सर्वोपरि है। मतदान से ही सरकारें बनती है। मतदाता ही तय करते हैं कि किस दल की सरकार देश और प्रदेश की उन्नति और विकास की गति को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। विपक्ष पर हमला बोलते हुये कहा सपा और कांग्रेस ने संविधान के नाम पर लोगो को गुमराह करने का काम किया। आपातकाल के हालातो को लेकर भी कांग्रेस पर हमला बोला। कहा भाजपा का एक एक कार्यकर्त्ता लोकसभा चुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन किया वह पूजनीय है। भितरघातियो से भी संगठन जल्द ही निपटेगी। उन्होंने केंद्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने पर मतदाताओं का अभिवादन किया।

जिलाध्यक्ष विवेकानन्द मिश्र ने कहा कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। कार्यकर्ता पार्टी की रीढ है। उनके ही मेहनत ने पूरे देश में रंग लाई है। आने वाले विधानसभा में हम भारी बहुमत से फिर सरकार बनायेंगे। लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेकर मतदाता ही देश में सरकार चुनते हैं। मतदाताओं ने देश में ऐतिहासिक रूप से नरेन्द्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाया है। सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं तथा उसके सही क्रियान्वयन पर जनता की मुहर लगी है। उन्होंने लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेने वाले सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त किया।

इस मौके पर यशकांत सिंह, राना नागेश सिंह, प्रत्युष विक्रम सिंह, दुष्यंत सिंह, कुँवर आनन्द सिंह, देवेन्द्र सिंह, चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, राम श्रिंगार ओझा, सुरेन्द्र सिंह, योगेन्द्र सिंह, वरुण सिंह, वीरेन्द्र गौतम, राम निवास गिरी, राजकुमार चौरसिया, श्यामनाथ चौध री, सुजीत सोनी, अतुल यादव, राकेश शर्मा, चंद्रभान गुप्ता, ओम प्रकाश शुक्ल, बलराम सिंह, विनय शंकर मिश्र, राम चरन चौधरी, रवि सिंह, मनोज ठाकुर, मगन शुक्ल, प्रबल मालानी, आनन्द सिंह कलहंस, वीरेन्द्र मिश्र, विनोद चौध री, भोला निषाद, विजय गुप्ता, वरुण पाण्डेय, राधेश्याम कमलापुरी, जटाशंकर शुक्ल, अरविन्द सिंह, राजेंद्र राजभर, मनोज पाठक, सुनील त्रिपाठी, श्रीश पाण्डेय, समीर चौहान, शिव चरन जायसवाल, मनीष सिंह, जवाहर लाल जायसवाल सहित मतदाता मौजूद रहे।

सीधा साधा सच्चा लिख,जो भी लिख, पर पक्का लिख।
मत लिख इनके—उनके जैसा, केवल अपने जैसा लिख।।
– बालसोम गौतम

डाक पंजीकरण संख्या बी.एस.टी.62 R.N.I. 40367/84

साप्ताहिक
आवाज दर्पण
प्रत्येक रविवार

भरण पोषण का हक

देश की शीर्ष अदालत ने महिला सशक्तीकरण की दिशा में नई पहल की है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मुस्लिम महिलाएं भी सीपीसी की धारा 125 के तहत भरण–पोषण की हकदार हैं। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने इस सिद्धांत की व्याख्या की कि भरण–पोषण किसी तरह का दान नहीं बल्कि सभी विवाहित महिलाओं का मौलिक अधिकार है। अब चाहे महिला किसी भी धर्म की क्यों न हो। दरअसल, अदालत का फैसला तेलंगाना के मोहम्मद अब्दुल समद की अपील के जवाब में आया है। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने भी इसी तरह का फैसला दिया था, जिसे शीर्ष अदालत ने बरकरार रखा। अब्दुल समद ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि एक तलाकशुदा महिला केवल मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत ही भरण–पोषण की मांग कर सकती है। शीर्ष अदालत ने उसकी अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट का मानना था कि धारा 125 देश की सभी महिलाओं पर लागू एक धर्मनिरपेक्ष प्रावधान है। उल्लेखनीय है कि यह फैसला ऐतिहासिक शाह बानो प्रकरण की याद ताजा करता है। इस मामले में शीर्ष अदालत ने धारा 125 के तहत एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला के भरण–पोषण के अधिकार के पक्ष में फैसला सुनाया था। यह फैसला 1986 के उस अधिनियम के बावजूद था, जिसमें इस अधिकार को सीमित करने के प्रावधान किये गये थे। बहरहाल, अदालत का हालिया फैसला धारा 125 की स्थायी स्वीकार्यता को सिद्ध करता है। यह भारतीय न्यायतंत्र की खूबसूरती ही है कि अधिनियम के विकास और उसके बाद के न्यायिक उदाहरणों ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के भरण–पोषण के अधिकारों का उत्तरोतर विस्तार ही किया है। निस्संदेह, शीर्ष अदालत का फैसला महिलाओं को उनके न्यायोचित अधिकार दिलाने तथा संरक्षण की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है।

बहरहाल, अदालत ने इस फैसले के जरिये यह संदेश देने का प्रयास किया है कि जब हम 21वीं सदी में सर्वांगीण विकास व सभ्यता के समृद्ध होने का दावा करते हैं तो महिलाओं के अधिकारों को लेकर भी हमारी सोच प्रगतिशील होनी चाहिए। उनके प्रति संकीर्ण मानसिकता के चलते ही महिलाओं की स्थिति में अपेक्षित बदलाव नहीं हो पाया है। अदालत का नवीनतम निर्णय विकास क्रम के अनुरूप यह सुनिश्चित करता है कि देश में किसी भी धर्म की महिला अपने अधिकारों से वंचित न रहे। साथ ही यह भी कि विवाह विच्छेदन के बाद भी महिला को भरण–पोषण के लिये आर्थिक सहायता पाने का अधिकार है। निस्संदेह, अदालत ने भारत में लैंगिक न्याय और समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। यह फैसला न केवल संवैधानिक सिद्धांतों को कायम रखता है बल्कि मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को भी मजबूत करता है। साथ ही यह फैसला भविष्य के मामलों के लिये भी एक मिसाल स्थापित करता है। इस फैसले का मानवीय पक्ष यह भी है कि यदि तलाकशुदा महिला का आय का कोई नियमित जरिया नहीं है तो भरण–पोषण के लिये आर्थिक मदद न मिल पाने से उसके जीवन–यापन का संकट बड़ा हो जाता है। विडंबना यह है कि भारत में मायके पक्ष के सक्षम होने के बावजूद तलाकशुदा बेटी को साथ रखने को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। जिससे तलाकशुदा बेटियों का जीवन–यापन दुष्कर हो जाता है। ऐसी महिलाओं के जीवन में यह फैसला एक नई रोशनी बनकर आया है। निस्संदेह, फैसला स्वागतयोग्य है और इसके दूरगामी गहरे निहितार्थ भी हैं। पिछली राजग सरकार के दौरान बने तीन तलाक कानून ने भी मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया था। यह फैसला देश की सोच में आए बदलाव का भी प्रतीक है। करीब चार दशक पहले शाह बानो केस में कोर्ट के ऐसे ही प्रगतिशील फैसले को तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने अपनी विधायी शक्ति से पलट दिया था।

बजट पर टिकी मध्यम वर्ग की निगाहें

-डा. जयंतीलाल भंडारी-

इन दिनों पूरे देश के साथ–साथ दुनिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की निगाहें 23 जुलाई को पेश किए जाने वाले वर्ष 2024–25 के पूर्ण बजट की ओर लगी हैं। हाल ही में आयी वैश्विक ब्रोकरेज कंपनी मार्गन स्टेनली की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के नए बजट में राजस्व व्यय के मुकाबले पूंजीगत खर्च पर जोर रहेगा और इससे मध्यम वर्ग लाभान्वित होते हुए दिखाई दे सकता है। साथ ही इसमें 2047 तक विकसित भारत के लिए खाका और राजकोषीय मजबूती के लिए मध्यम अवधि की योजना पेश की जा सकती है। नए बजट के जरिये मध्यम वर्ग की क्रयशक्ति बढ़ाकर मांग में वृद्धि करके अर्थव्यवस्था को गतिशील करने की रणनीति पर आगे बढ़ा जा सकता है।

मध्यम वर्ग को राहत देने को लेकर लगातार मांग तेज हुई है। विगत वर्षों में जहां गरीब वर्ग के लिए राहतों का ऐलान किया गया, वहीं कॉर्पोरेट जगत पर भी ध्यान दिया। लेकिन राहत पाने के मामले में सबसे अधिक टैक्स देने वाला मध्यम वर्ग पीछे छूट गया। 18वीं लोकसभा चुनाव के मतदान में मध्यम वर्ग की नाराजगी भी दिखाई दी है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री के संबोधन में जिक्र था कि मध्यम वर्ग कैसे कुछ बचत बढ़ा सके तथा इस वर्ग के लोगों की जिंदगी को कैसे आसान बनाया जा सके, इस परिप्रेक्ष्य में रणनीति पूर्वक आगे बढ़ा जाएगा। गौरतलब है कि इस पूर्ण बजट 2024–25 के समय आयकर संबंधी मजबूत परिदृश्य मौजूद है। पिछले 10 वर्षों में आयकर रिटर्न भरने वाले आयकरदाताओं की संख्या और आयकर की प्राप्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। साल 2023–24 में आयकर रिटर्न रिकॉर्ड 8 करोड़ के स्तर को पार कर चुका है और बीते 10 साल में आयकर रिटर्न भरने वाले दोगुने से अधिक हुए हैं। आयकर विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, 2013–14 में आयकर संग्रह करीब 2.38 लाख करोड़ रुपये था। यह फिर तेजी से बढ़ता गया। यह वर्ष 2019–20 में 10.5 लाख करोड़ रुपये हो गया। कोरोनाकाल के कारण यह 2020–21 में कुछ घटा। लेकिन 2021–22 में 14.08 करोड़ रुपये, 2022–23 में 16.64 करोड़ रुपये और वर्ष 2023–24 में 19.58 करोड़ रुपये हो गया।ऐसी मजबूत वित्तीय मुट्ठी से आयकर के नए और पुराने दोनों स्लैब की व्यवस्थाओं के तहत करदाताओं व मध्यम वर्ग को राहतों से लाभान्वित किया जा सकता है। खासतौर से वेतनभोगी वर्ग को लाभान्वित करने के भी विशेष प्रावधान नए बजट में दिखाई दे सकते हैं। इसके तहत मानक कटौती यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये तक किया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2018 में मानक कटौती की सीमा 40 हजार रुपये थी और वर्ष 2019 में इसे बढ़ाकर 50 हजार रुपये किया गया था। मानक कटौती वह धनराशि है, जिसे वेतनभोगी करदाता अपनी कर योग्य आय में से बिना कोई सबूत दिए घटा सकता है। टीडीएस के कारण वेतनभोगी अपने वेतन पर ईमानदारी से आयकर चुकाते हैं जहां आमदनी कम बताने की गुंजाइश नगण्य होती है। वेतनभोगी वर्ग द्वारा नए बजट में राहत की अपेक्षा इसलिए भी न्यायसंगत है कि इस वर्ग द्वारा दिया गया कुल आयकर पेशेवरों और कारोबारी करदाता वर्ग द्वारा चुकाए गए आयकर से काफी अधिक होता है।

नए बजट के तहत आयकर से संबंधित विभिन्न टैक्स छूटों में वृद्धि की जा सकती है। मौजूदा समय में धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये की छूट मिलती है। इसके तहत ईपीएफ, पीपीएफ, एनएससी, जीवन बीमा, बच्चों की ट्यूशन फीस और होम लोन का मूलधन भुगतान भी शामिल है। मकानों की बढ़ती हुई कीमत को देखते हुए धारा 80सी के तहत 2.5 लाख से तीन लाख की छूट दी जा सकती है। इसी तरह इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80डी के तहत कर कटौती की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। 80डी के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट बढ़ सकती है ताकि टैक्सपेयर्स हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर प्रेरित हों। इसके साथ–साथ वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सीमा बढ़ाई जाने से लोगों को स्वास्थ बीमा कराने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। वहीं पीपीएफ में योगदान की वार्षिक सीमा को मौजूदा 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया जा सकता है।

निःसंदेह देश में कर सुधारों से आयकर संग्रहण में आशातीत वृद्धि हुई है। लेकिन अभी आयकर के दायरे में इजाफा किए जाने की बड़ी संभावनाएं हैं। जहां वर्ष 2024–25 के बजट से आयकर राहत दी जा सकती है, वहीं बजट में आयकर के दायरे का विस्तार करने की नई रणनीति का ऐलान संभव है। महत्वपूर्ण यह भी कि बड़ी संख्या में उद्योग–कारोबार सेक्टर में कार्यरत रहते हुए कमाई करने वाले, महंगी व विलासिता की वस्तुओं का उपयोग करने वाले तथा पर्यटन के लिए विदेश यात्राएं करने वालों में से बड़ी संख्या में लोग या तो आयकर न देने का प्रयास करते हैं या फिर बहुत कम आयकर देते हैं। रिपोर्टों के मुताबिक, पिछले एक वर्ष में करीब 24 लाख लोगों ने 10 लाख रुपये से ज्यादा महंगी कारें खरीदी, करीब 25 लाख लोगों ने 50 लाख रुपये से अधिक कीमत के महंगे घर खरीदे वहीं वर्ष 2022 में देश के करीब 2.16 करोड़ लोगों ने पर्यटन के मद्देनजर विदेश यात्राएं कीं। जाहिर है पर्याप्त कमाई के कारण ही ये खरीदियां और विदेश यात्राएं संभव हैं। लेकिन ऊंची कमाई करके भी बड़ी संख्या में लोग आयकर नहीं देना चाहते। बता दें कि वर्ष 2023–24 में देश के 140 करोड़ से अधिक लोगों में से सिर्फ 2.79 करोड़ लोगों ने ही आयकर दिया है। यानी देश की आबादी के 1.97 फीसदी लोगों ने ही आयकर दिया है। ऐसे में आयकर का पूरा बोझ दो फीसदी से भी कम आबादी द्वारा उठाया जा रहा है। साथ ही देश में कुल आयकर रिटर्न के करीब 70 फीसदी आयकर रिटर्न शून्य आयकर देयता बताते हुए दिखाई दिए हैं। ऐसे में देश में आयकर संग्रहण सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आकार की तुलना में महज 11.7 फीसदी ही है। जबकि यह जर्मनी में 38 फीसदी, जापान में 31 फीसदी, ब्रिटेन में 25 फीसदी, अमेरिका में 25 फीसदी और चीन में 18 फीसदी है। वहीं अमेरिका की 60 फीसदी और ब्रिटेन की 55 फीसदी आबादी आयकर चुकाती है। दुनिया की कई छोटी–छोटी अर्थव्यवस्थाओं में संगृहीत किए जाने वाले आयकर का उनकी जीडीपी में बड़ा योगदान है।उम्मीद करें कि इस बार वित्तमंत्री नए बजट से ऐसे लोगों को चिन्हित करने की नई रणनीति के साथ दिखाई देंगी, जिससे वास्तविक आमदनी का सही मूल्यांकन हो सके, लोगों के वित्तीय लेनदेन के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही जो वास्तविक कमाई से कम पर आयकर देते हैं, उन्हें भी चिन्हित करके अपेक्षित आयकर चुकाने के लिए बाध्य किया जा सके। निश्चित रूप से इससे देश में टैक्स संग्रहण बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

—लेखक अर्थशास्त्री हैं।

नीट परीक्षा में धांधली, पेपर लीक के सवालों को लेकर राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन

संवाददाता–बस्ती। शुक्रवार को बहुजन मुक्ति पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने आये दिन होने वाले पेपर लीक और नीट परीक्षा में धांधली के सवाल को लेकर बहुजन मुक्ति पार्टी युवा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष चन्द्र प्रकाश गौतम के नेतृत्व में शास्त्री चौक पर धरना दिया गया। धरने के बाद जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर समस्याओं के निस्तारण की मांग किया गया। धरने को बहुजन मुक्ति पार्टी के मण्डल अध्यक्ष हृदय गौतम, भारत मुक्ति मोर्चा जिलाध्यक्ष आर.के. आरतियन ने सम्बोधित किया। कहा कि पेपर लीक के कारण युवाओं का भविष्य चौपट हो रहा है। इसे तत्काल रोका जाय।

राष्ट्रपति को भेजे ज्ञापन में नीट परीक्षा की धांधली में जो लोग पकड़े गए हैं उन पर कड़ी कार्यवाही किये जाने, परीक्षा निजीकरण के स्थान पर सरकारी प्रशासन के नियंत्रण करायी जाय, दुबारा परीक्षा निःशुल्क और निष्पक्ष कराई जाए तथा किसी भी परीक्षार्थी से इस वार किसी भी प्रकार की कोई भी फीस न ली जाने, धांधली करने वाले निजी संस्थाओं पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित लगाये जाने, धांधली में जो शासन प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी है उन पर कड़ी कार्रवाई किये जाने आदि की मांग शामिल है। धरना और ज्ञापन सौंपने वालों में लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी ठाकुर प्रेमनन्दबंशी, रितिक कुमार, बुद्धेश राना, विमला देवी, डा. रिफाकत अली, मो. जावेद, सुनील कन्नौजिया, कुंवर भीम सिंह, रामलैस के साथ ही अनेक लोग शामिल रहे।

जूनियर शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन, ऑन लाइन हाजिरी का फैसला वापस ले सरकार

संवाददाता–बस्ती। शुक्रवार को उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल 'पूर्व माध्यमिक' शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष अम्बिका पाण्डेय के नेतृत्व में जिला अधिकारी द्वारा नामित उप जिलाधिकारी सुनिष्ठा सिंह को मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन सौंपा। मांग किया कि ऑन लाइन डिजिटलाइजेशन के निर्णय को वापस लिये जाने के साथ ही शिक्षक समस्याओं का प्रभावी निस्तारण कराया जाय।

ज्ञापन सौंपने के बाद अम्बिका पाण्डेय ने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन विद्यालय की पंजीकाओं का डिजिटलाइजेशन व डिजिटल (डिजिटल फेस छायांकन) उपस्थिति कराए जाने संबंधी निर्देश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाय। कहा कि पिछले 4 दिनों से समूचे प्रदेश के लगभग 6 लाख शिक्षक डिजिटलाइजेशन का मुखर विरोध कर रहे हैं इसके बावजूद सरकार और परिषदीय अधिकारियों की चुप्पी हैरान करने वाली है। कहा कि सरकार मांगों को तत्काल पूरा करने की दिशा में पहल करे।

मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में जूनियर हाई स्कूल के शिक्षक, शिक्षिकाओं को हॉफ सी०एल० की सुविधा दिये जाने, 30 ई०एल० की सुविधा देने, कैशलेस चिकित्सा सुविधा (बिना प्रीमियम) दिये जाने, ससमय स्थानानतंरण, पदोन्निति किये जाने, वेतन विसंगति समस्या का निराकरण करने, लिपिक की नियुक्ति करने, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति करने, परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक, शिक्षिकाओं को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किये जाने, शिक्षक, शिक्षिकाओं के जनपद स्तर की स्मस्याओं को निस्तारित किये जाने आदि की मांग शामिल है।

ज्ञापन सौंपने वालों में मंत्री मोहम्मद इजहारूल हक, कोषाध्यक्ष प्रदीप कुमार जायसवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रमोद कुमार त्रिपाठी, उमेश मौर्य, मोहम्मद आलम, फूलचंद, डा. राजेश सक्सेना, बृजेश कुमार, विश्राम राव आशुतोष कुमार पाण्डेय, जया कुमारी, मनीष कुमार मिश्रा, संतोष श्रीवास्तव, राजेन्द्र प्रसाद, संतोष कुमार, अशोक राव, कृपा शंकर, बाबू लाल, आदि संगठन के पदाधिकारी एवं शिक्षक मौजूद रहे।

कुछ सभासदों ने किया नगर पालिका परिषद बोर्ड की बैठक का बहिष्कार, लगाये गंभीर आरोप

संवाददाता–बस्ती। शुक्रवार को नगर पालिका परिषद बोर्ड की बैठक को हंगामे के चलते स्थगित कर दिया गया। कुछ सभासदों ने सभासद रमेश कुमार गुप्ता, गौतम यादव, राजन ठाकुर, पंकज चौधरी, कृष्ण कुमार चौधरी के नेतृत्व में नगर पालिका में मनमानी का गंभीर आरोप लगाते हुये बोर्ड की बैठक का बहिष्कार कर दिया। नाराज सभासदों का कहना है कि नगर पालिका अध्यक्ष नेहा वर्मा की जगह उनके जेठ विवेक वर्मा काम काज देखते हैं और 25 वार्डो में योजनाओं का मनमाने तरीके से वितरण कराया जाता है। कुछ वार्डो में सर्वाधिक धन के प्रस्ताव स्वीकृत होते हैं तो कई वार्ड अछूते रह गये हैं। इसे बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। आखिर सभासद अपने वार्डो में जनता को क्या मुंह दिखाये। नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी तक की तैनाती नहीं कराया गया।

प्रेस को जारी विज्ञप्ति के माध्यम से बोर्ड की बैठक का बहिष्कार करने वाले रमेश कुमार गुप्ता, कृष्ण कुमार चौधरी आदि ने कहा कि बरसात के दिनों में अनेक वार्डो में नालियों की साफ–सफाई नहीं हो पा रही है। वार्डो में जल जमाव है। नागरिकों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। कई वार्डो के टोटियों में जल पिछले एक वर्ष नहीं आ रहा है। अनेकों बार शिकायत की गई किन्तु समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। पटल सहायकों द्वारा कार्यो को ठीक ढंग से नहीं किया जाता। मांग किया कि सभी 25 वार्डो में विकास कार्यो के समान वितरण के साथ ही पुनः बोर्ड की बैठक बुलाकर समस्याओं का प्रभावी निस्तारण कराया जाय।

बोर्ड के बैठक का बहिष्कार करने वालों में रमेश कुमार गुप्ता, राजन ठाकुर, पंकज चौधरी, कृष्ण कुमार चौधरी, गौतम यादव, रविन्द्र कुमार, ममता सोनकर, रोली चौधरी, अमरावती देवी, निर्मला देवी, रूकैय्या खातून, इन्द्रावती देवी, विद्यावती सोनकर, बैजन्ती सिंह, लारा चौधरी, अरविन्द सोनकर, शोभी सोनकर, प्रमोद गुप्ता, अभीजीत सिंह, उमेश प्रजापति के साथ ही सभासद और उनके प्रतिनिधि शामिल रहे।

नेपाल में गिरी पुष्प कमल दहल सरकार

काठमाण्डू (आभा)। नेपाल की राजनीति में बड़ी हलचल मच गई है। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दलह प्रचंड ने इस्तीफा दे दिया है और के पी शर्मा ओली का नया पीएम बनना लगभग तय हो गया है। संसद में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने विश्वास मत खो दिया। दरअसल, सीपीएम–यूएमल ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। 275 सदस्यों वाले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव (एचओआर) में प्रचंड के विश्वास मत के खिलाफ 194 और समर्थन में 63 वोट पड़े। विश्वास मत हासिल करने के लिए 138 मतों की आवश्यकता थी।

पिछले ही सप्ताह पूर्व प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सीपीएन–यूएमएल ने प्रचंड सरकार से समर्थन वापल ले लिया था। ओली और नेपाली कांग्रेस (नेकां) के नेताओं ने प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' के शुक्रवार को होने वाले शक्ति परीक्षण से पहले नई गठबंधन सरकार के गठन पर मंथन किया था। आपको बता दें के नेकां के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा ने पहले ही ओली को नेपाल के अगले प्रधानमंत्री के रूप में अपना समर्थन दिया है।

अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत अभी जेल में ही रहेंगे

नई दिल्ली (आभा)। दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. ईडी वाले मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 3 जजों वाली बेंच को भेज दिया है. बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी. भले ही केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है लेकिन उनपर केस चलता रहेगा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार अरविंद केजरीवाल को बेल मिली है. लेकिन मुकदमा खारिज नहीं हुआ है. इस कारण मुख्यमंत्री केजरीवाल पर मुकदमा चलता रहेगा. इसी बीच दिल्ली भाजपा ने बिजली के मुद्दे पर आप सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकाला. इस दौरा भाजपा के नेता आरपी सिंह ने कहा कि 'जांच एजेंसी और न्यायपालिका के बिच का निर्णय है. और अंतरिम बेल मिलने का मतलब ये नहीं होता की आप अपराध मुक्त हो गए हैं।

मालूम हो कि उच्चतम न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर ईडी की गिरफ्तारी की शक्तियों से संबंधित तीन सवाल उठाए, मामला बड़ी पीठ के पास भेजा. आप नेता संजय सिंह ने शुक्रवार को आबकारी नीति घोटाला मामले में ईडी द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जश्न मनाया. उन्होंने लिखा, 'मोदी जी, झूठे मामले दर्ज करके सच्चाई को कब तक कैद रखेंगे? पूरा देश आपकी तानाशाही देख रहा है. चाहे ईडी कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, सभी का मानना है कि केजरीवाल को ईडी ने झूठे मामले में फंसाया है. सुप्रीम कोर्ट का फैसला सच्चाई की जीत है।

स्मृति इरानी के बचाव में आगे आये राहुल गांधी

नई दिल्ली (आभा)। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेठी से पूर्व सांसद स्मृति ईरानी को लेकर सोशल मीडिया पर हो रही टिप्पणी पर नाखुशी जाहिर की है।

उन्होंने एक्स पर कहा कि जीत और हार जीवन का हिस्सा हैं। मैं सभी से अपील करता हूं की स्मृति ईरानी के खिलाफ किसी भी तरह की अपमानजनक भाषा का प्रयोग न करें। किसी को बेइज्जत और शर्मसार करना कमजोर होने की निशानी है ताकतवर होने की नहीं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि ऐसा न करें।

बता दें कि भाजपा नेता स्मृति ईरानी मोदी सरकार के पहले दो कार्यकाल में मंत्री रह चुकी हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी में राहुल गांधी को हराने के बाद उनका कद काफी बढ़ गया था। हालांकि, 2024 के चुनाव में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के करीबी किशोरी लाल शर्मा के सामने उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। नई सरकार में उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह भी नहीं मिली।

पूर्व केंद्रीय मंत्री को अपना सरकारी आवास खाली करना पड़ा है जिसके बाद से वह सोशल मीडिया पर लगातार निशाने पर हैं। इसे लेकर राहुल गांधी ने एक्स पर टिप्पणी की है।

कुछ सभासदों का आक्रोश स्वाभाविक, मिल बैठकर होगा समस्याओं का समाधान– नेहा वर्मा

संवाददाता–बस्ती। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष नेहा वर्मा ने शुक्रवार को आयोजित बोर्ड की बैठक का कुछ सभासदों द्वारा बहिष्कार किये जाने पर प्रतिकिया व्यक्त करते हुये कहा कि सभासदों की मांग जायज है और वे लगातार प्रयास कर रही है कि नगर पालिका परिषद में अधिशासी अधिकारी कार्यभार संभाले। इस सम्बन्ध में विभागीय स्तर पर पत्राचार के साथ ही व्यक्तिगत रूप से नगर विकास मंत्री से मिलकर आग्रह किया गया है कि अति शीघ्र अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति सुनिश्चित किया जाय।

प्रेस को जारी विज्ञप्ति के माध्यम से पालिका अध्यक्ष नेहा वर्मा ने कहा कि कार्य भार संभालने के बाद से ही उनका प्रयास रहा है कि नागरिकों से जो वायदे किये गये हैं उस अनुरूप कार्य धरातल पर कराया जाय। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बस्ती आगमन पर उन्हे सीवर लाइन, सड़कों के निर्माण और गांधीनगर में मल्टीलेबल पार्किंग का निर्माण कराने हेतु प्रस्ताव दिया गया है जिस पर मुख्यमंत्री जी ने शीघ्र पहल का आश्वासन दिया गया है। अध्यक्ष नेहा वर्मा ने कहा कि सभी 25 वार्डों के समुचित विकास, नाली, खण्डजा निर्माण, साफ–सफाई प्रकाश व्यवस्था आदि का कार्य कराया जाता है। अधिशासी अधिकारी द्वारा कार्यभार न संभाले जाने को लेकर सभासदों का गुस्सा स्वाभाविक है। कहा कि उनका पूरा प्रयास है कि असहमतियों को दूर करने के साथ ही प्रभावी ढंग से अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति सुनिश्चित हो जिससे विकास कार्यों को गति दी जा सके। सभी वार्डों का समुचित और संतुलित विकास उनकी प्राथमिकता है। कहा कि सभासदों की नाराजगी को मिल बैठकर दूर कर लिया जायेगा। अति शीघ्र पुनः बोर्ड की बैठक बुलाई जायेगी।

रुपईडीहा भारतीय इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट के तीन अधिकारी बर्खास्त

संवाददाता–बहराइच। लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रुपईडीहा स्थित इंटीग्रेटेड चेकपोर्स्ट के तीन उच्चाधिकारियों को पद से ही बर्खास्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई आईसीपी की देखभाल की जिम्मेदारी संभाल रही कंपनी के चेयरमैन ने नेपाल की महिला के सोशल मीडिया पर वायरल किए गए वीडियो के आधार पर की है। बिना जांच उच्चाधिकारियों को पद से हटाने की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है।

भारत–नेपाल सीमा पर दोनों देशों के बीच सामरिक, व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने व पारदर्शी बनाने के लिए भारत सरकार की पहल पर रुपईडीहा बार्डर पर आईसीपी यानि इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट का संचालन शुरू किया गया है। भारतीय क्षेत्र के आईसीपी के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भारत सरकार की ओर से दिल्ली की संडलियाम कंपनी को सौंपा गया है। आईसीपी के संचालन को अभी चार माह हुए हैं, इस बीच कर्मचारियों की तैनाती को लेकर कंपनी विवादों के घेरे में है।

पहले कर्मियों की ओर से शोषण के आरोप लगाए गए अब सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की बिना जांच किए कंपनी के चेयरमैन की ओर से प्रबंधक, सुरक्षा अधिकारी व तकनीकी अधिकारी को पद से ही हटा दिया है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले नेपाली महिला आईसीपी से होकर जा रही मैत्री बस से वतन वापस जा रही थी। आईसीपी पर जांच के दौरान किसी कर्मी ने उसका वीडियो बना लिया।

महिला के विरोध करने पर प्रबंधक की ओर से जांच कराई गई। जिसके बाद वीडियो को डिलीट कराकर मामला शांत हो गया। किसी ने महिला का वीडियो गलत तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जिसको गंभीरता से लेते हुए प्रबंधक बीएस सिसोदिया, सुरक्षा अधिकारी वंशराज, टेक्निकल इंजीनियर नवजोत सिंह को बर्खास्त कर दिया है। हटाए गए तीनों अधिकारियों का आरोप है कि बिना उनका पक्ष जाने व वायरल वीडियो की जांच के ही कार्रवाई की गई है। हालांकि 15 जुलाई को चेयरमैन के समक्ष प्रस्तुत होकर अपना पक्ष रखेंगे। वैसे कंपनी ने तत्काल प्रभाव से प्रबंधक पद पर वेद प्रकाश ज्वेल की तैनाती कर दी है, ताकि आईसीपी के संचालन में कोई दिक्कत न हो। हालांकि यह कार्रवाई चर्चा का विषय बनी हुई है।

नेपाली महिला ने बताया कि जिस वीडियो के आधार पर आईसीपी के अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। उस महिला का पक्ष आया है। नेपाली महिला ने वीडियो को गलत तरीके से प्रसारित करने का आरोप लगाया है। ऐसे में तीन अधिकारियों को पद से हटाने की कार्रवाई पर लोग सवाल उठा रहे हैं।

एमडी ने कहा कि आईसीपी के संचालन को सिर्फ अभी चार माह हुए हैं। इस दौरान 14 कर्मचारियों को बिना किसी वजह के निकाला गया है। नामित कंपनी की ओर से उठाए गए कदम से लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। विजय कुमार त्रिपाठी, सुखवीर सिंह, शुभम त्रिपाठी, प्रभाकर, आशीष त्रिपाठी, अदित्य सिंह, विनय मिश्र, सिमरन गुप्ता, भीमराज मौर्य, नरेंद्र कुमार यादव, रविन्द्र प्रताप सिंह, दीपमाला वर्मा व अर्जुन वर्मा का आरोप है कि दो माह का वेतन दिए बिना ही उनको हटा दिया गया है। अब वे लोग हक की लड़ाई के लिए आईसीपी पर प्रदर्शन करेंगे। आईसीपी का बेहतर तरीके से संचालन को लेकर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। लापरवाह लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। पूरी पारदर्शिता से काम किया जा रहा है।

मेरा तो बेटा भी गया और इज्जत भी, शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के माता-पिता का छलका दर्द, बहू ने छोड़ा परिवार

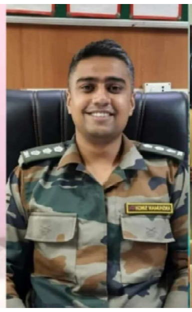

संवाददाता–देवरिया। कैप्टन अंशुमन के पिता की दर्द भरी दास्तां जानकर आप भी विचलित हो सकते हैं। आंखों में आंसुओं का सैलाब लेकर एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में शाहिद के पिता ने जो कहा वह हर किसी को हिला कर रख देगा। कैप्टन अंशुमान सिंह ने आग में फंसे अपने साथियों को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। उनके इस बहादुरी भरे पराक्रम के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें कीर्ति चक्र से (मरणोपरांत) सम्मानित किया। लेकिन आंखों में आंसुओं का सैलाब लेकर कैप्टन अंशुमान सिंह के माता–पिता ने एक चौनल को दिए गए इंटरव्यू में अपनी बहू पर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उनका बेटा भी चला गया। उनकी बहू अब उनका परिवार छोड़ कर चली गई। वह अपने साथ सब कुछ ले गई। राष्ट्रपति मुर्मू ने दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह में दिवंगत अधिकारी की पत्नी स्मृति और मां मंजू सिंह को कैप्टन अंशुमान सिंह की शहादत पर कीर्ति चक्र प्रदान किया। यह शांतिकाल में वीरता के लिए दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। कीर्ति चक्र प्राप्त करने के बाद शहीद कैप्टन की पत्नी स्मृति ने अपनी लव स्टोरी को सुनाई थी। वह उस समय काफी भावुक भी दिखी थीं। लेकिन अब शाहिद के पिता का बहू पर लगाए गए आरोप आपके रोंगटे खड़ा कर देंगे। एक तरफ बेटा चला गया पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब बहू भी परिवार का साथ छोड़कर चली गई। शहीद के पिता का कहना है कि उन्हें इस बात की भनक तक नहीं लगी कि मेरी बहू मेरे परिवार का साथ छोड़कर क्यों चली गई। पिता ने बताया कि 18 तारीख को हमारी अंशुमान से एक दो मिनट की बात हुई। 19 तारीख को घटना हुई और हमारा बेटा शहीद हो गया। उन्होंने कहा कि 1 फरवरी को शांति पूजा कराया उसमें भी वह नहीं आई। जब भी हम लोग फोन करते हैं। फोन परिवार के लोग उठाते हैं। सिर्फ एक ही जवाब मिलता है अभी बेटी को संभालने के लिए थोड़ा समय दीजिए। करीब 1 साल हो गए मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि वह अब तक संभाल पाई कि नहीं कैप्टन के पिता ने आगे बताया कि मेरे घर से जाने के 10 दिन बाद वह एक स्कूल में पढ़ने लगी। जिसकी मनोस्थिति ठीक नहीं होगी। वह किसी स्कूल में पढ़ा कैसे सकता है। शहीद के पिता रवि प्रताप सिंह ने अपने बेटे के ससुराल वालों पर भी बड़ा आरोप लगाया उन्होंने कहा कि यह सब कुछ उन लोगों के इशारे पर हुआ है। कहा कि उनकी बहू यहां से जाने के बाद फोन तक नहीं उठाती है। उसने अचानक परिवार का साथ छोड़ दिया। बीते 26 जनवरी को जब उनके बेटे को सम्मान देने की बात हुई तो तभी उनकी बहू से बात हुई। इस दौरान हमने घर पर पूजा करने की भी बात बताई। लेकिन वह पूजा में भी नहीं आई। मेरी बहू स्मृति अपना सारा सामान पैक कर अपने साथ ले गई। आंखों में आंसुओं की धार लिए शहीद के पिता ने कहा कि मेरा बेटा मेरी बहू स्मृति से बहुत प्यार करता था। लेकिन उसने प्यार की परिभाषा और मर्यादा को भी तोड़ दिया। अब तो मेरा बेटा भी चला गया बहू भी चली गई। साथ में मेरी इज्जत भी चली गई। कैप्टन की मां ने चौनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि मेरी बहू नोएडा वाले मकान में रहती थी। जब मेरी बेटी यहां से गई तो पता चला कि मेरी बहू अपना सारा सामान पैक करके चली गई। पिता ने कहा कि आर्मी की एक प्रक्रिया है उसके मुताबिक निकटतम परिजन को मुआवजा मिलता है। इसका एक बड़ा हिस्सा उनकी बहू को मिला पेंशन उन्हें मिलेगी। इंश्योरेंस में दोनों को बराबर मिला। उत्तर प्रदेश सरकार से 35 लाख उनकी बहू को मिला 15 लाख उन्हें मिले। मां ने कहा कि अब उनकी बहू कह रही है कि पैसा हमें सरकार से मिल रहा है।

चौकीदार पर वसूली का आरोप, एसपी से शिकायत

संवाददाता–बहराइच। अभी तक पुलिस महकमे में प्राइवेट वाहन चालकों से धन वसूलने के किस्से सुनने में आते रहे हैं। अब गांव का एक लाल गमछाधारी चौकीदार भी नकदी व गोश्त भेजने का फरमान भेज रहा है। मांग पूरी न होने पर फर्जी केस में फंसाने की धमकी भी दी। जिसके बेअसर होने पर जबरन पीड़ित के दो बकरे खुलवा लिए। मामला तूल पकड़ने पर पुलिस इसे रफा–दफा करने की जुगत भिड़ा रही है। हुजूरपुर थाने के भूपानी ग्राम निवासनी मोमिना पत्नी मुस्तफा उर्फ अंगनू ने पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र सौंपा है। आरोप है कि गांव के चौकीदार ने पहले फोन पर उनके पति से एक हजार रुपए व गोश्त की मांग की। मांग पूरी न करने पर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। जब यह धमकी भी बेअसर रही, तब चौकीदार व उसके सहयोगी जबरदस्ती घर से दो बकरियां उठा ले गए। जिनकी कीमत 15 हजार रुपये है। पीड़िता का आरोप है कि उसने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस अपने चौकीदार को बचाने में लगी है। महिला ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर चौकीदार का एक धमकी भरा आडियो भी वायरल किया है।

जिसमें चौकीदार अपनी रौब दिखाता सुनाई पड़ रहा है। पुलिस ने मामला तूल पकड़ता देख नई स्क्रिप्ट तैयार की है। जिसमें दोनों पक्षों के विवाद को सुलह होना बताया है। पीड़िता का कहना है कि यह गलत है। हल्के में तैनात सिपाही व चौकीदार सुलह को धमका रहे हैं।

पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया मनी लान्ड्रिंग का केस

संवाददाता–बलरामपुर। बलरामपुर जिले के सादुल्लाहनगर के पूर्व सपा विधायक आरिफ अनवर हाशमी पर शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने पूर्व विधायक पर मनी लांड्रिंग का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इनके ऊपर 32 मुकदमे दर्ज हैं। जिले के टॉप टेन माफिया की सूची में इनका नाम है। प्रशासन ने अब तक इनकी करीब 120 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त किया है।

आरिफ अनवर हाशमी बलरामपुर जिले के सादुल्लाहनगर थाने के अहिरौली गांव के रहने वाले हैं। वर्ष 2007 से 2012 तक सादुल्लाहनगर विधानसभा सीट से सपा के विधायक रहे। इनके खिलाफ बलरामपुर जिले के विभिन्न थाने में 32 मुकदमे दर्ज हैं। जिनमें अधिकांश मुकदमे जमीन हड़पने के है। थाने की जमीन कब्जा किए जाने के मामले में बीते वर्ष तत्कालीन डीएम अरविंद सिंह ने जांच कराई जांच के बाद इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। साल 2023 में लखनऊ, उतरौला और सादुल्लाहनगर को मिलाकर इनकी करीब 120 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। इसी वर्ष बलरामपुर जिले के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने इनकी संपत्ति जांच करने की संस्कृति की थी। बैंक खातों में जमा धनराशि जमीन, मकान वाहन सहित अन्य प्रॉपर्टी के खरीदे बेचे जाने को लेकर लिखा पढ़ी की गई थी। पुलिस की रिपोर्ट के बाद ईडी ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिससे परिवार और उनके समर्थकों में हड़कंप मच गया है।

बलरामपुर पुलिस के अधिकारी सिर्फ इस बात की पुष्टि कर रहे हैं यहां से रिपोर्ट भेजी गई है।

मोदी और योगी के अनुरूप विकसित हो रही है अयोध्या -रोली सिंह

संवाददाता—अयोध्या। जिला पंचायत अध्यक्ष अयोध्या रोली सिंह के 3 वर्ष पूरे होने पर अयोध्या के सर्किट हाउस में प्रेस से मुखातिब हुई और अपने 3 वर्ष की विकास कार्यों को बताया उन्होंने सर्वप्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और कहां की अयोध्या सांस्कृतिक राजधानी है और इसका विकास प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। उन्होंने देव तुल्य जनता जनार्दन का आभार व्यक्त कया और कहा कि प्रथम दिन से उनके विकास के लिए कार्य कर रही हूं और जो भी समस्या मेरी समक्ष रखी जाती है या मुझे मालूम पड़ती है उसका तुरंत निस्तारण करती हूं। उन्होंने कहा कि 3 वर्ष के कार्यकाल में अयोध्या जिला पंचायत को ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य किया है और अभी भी प्रयत्नशील हूं। उन्होंने बताया कि जनपद के प्राथमिकता के कार्यों में से ग्रामीण मार्गो के मरम्मत, गड्ढ़ा मुक्ति के अन्तर्गत वर्ष 2023—24 में 35.750 किमी0 तथा कुल तीन वर्षों में 77.877 किमी० सड़कों का नवीनीकरण कार्य कराकर सुगम आवागमन हेतु जनता जर्नादन को समर्पित किया गया।

उन्होंने बताया कि ग्रामीण मार्गो पर वर्ष 2023—24 में 2.620 किमी0 तथा कुल तीन वर्षों में 16.52 किमी० सड़कों का नवनिर्माण,ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2023—24 में 9.061 किमी० सी०सी० रोड तथा कुल तीन वर्षों में 19.881 किमी० सड़कों पर सी०सी० रोड का निर्माण किया गया। 2023—24 में 20. 686 किमी० खडण्जा रोड तथा कुल तीन वर्षों में 45.546 किमी0 सड़कों पर खडण्जा रोड का निर्माण कार्य कराया गया। ग्रामीण क्षेत्र में जल निकासी के लिए 2023—24 में 9.747 किमी० आर०सी०सी० नाला एवं कुल तीन वर्षो में 23.054 किमी० आर०सी०सी० नालों का निर्माण कराकर जनता जर्नादन को अर्पित की जा चुकी है और जल संरक्षण के उद्देश्य की पूर्ति हेतु अमृत सरोवरों का निर्माण कराया गया है।ग्रामीण क्षेत्रो के विभिन्न ग्राम पंचायतों में पथ प्रकाश की व्यवस्था हेतु 5807 एल०ई०डी० लाइटों को लगवाया जा चुका है तथा और लाइटें लगवाये जाने का कार्य प्रगति पर है और जिला पंचायत कार्यालय परिसर में जन सहयोग से मा० अटल बिहारी बाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण मा० उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्या के कर कमलों द्वारा मा० अध्यक्ष, जिला पंचायत अयोध्या की अध्यक्षता में किया गया तथा पार्को का सौन्दर्यकरण कार्य भी कराया गया। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार और जिला पंचायत के सभी सदस्य जनता के प्रति समर्पित होकर के निरंतर कार्य कर रहे हैं।

इस अवसर पर जिला अध्यक्ष संजीव सिंह महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव, पूर्व पूर्व महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा, रुदौली के वर्तमान विधायक रामचंद्र यादव, मिल्कीपुर के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा और जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि आलोक सिंह उपस्थित रहे।

मुख्य न्यायाधीश ने रामलला के दरबार में लगाई हाजिरी

संवाददाता—अयोध्या। भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। उन्होंने राम मंदिर की भव्यता को भी निहारा। भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे। उन्होंने रामलला व हनुमंतलला के दरबार में हाजिरी लगाई। इससे पहले अपराह्न 3:15 बज वे महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर उतरे। वहां से व्यापक सुरक्षा प्रबंधों के मध्य वे सरयू तट स्थित पर्यटन विभाग के होटल गए। जहां थोड़ी देर विश्राम के बाद वे सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी पहुंचे। यहां करीब 20 मिनट तक पूजा—अर्चना के बाद राममंदिर के लिए रवाना हुए। रामलला के दरबार में उन्होंने करीब 15 मिनट तक पूजा—अर्चना की। उन्होंने राममंदिर की भव्यता को भी निहारा। उन्हें मंदिर निर्माण के कार्यों के बारे में भी बताया गया। करीब ढ़ाई घंटे तक वे अयोध्या में रहे और शाम को 5:30 बजे चौधरी चरण सिंह घाट स्थित हैलीपैड से हेलीकाप्टर के जरिये वापस हो गए।

ऊफनाई राप्ती, रेगुलेटर से पानी के रिसाव से मचा हड़कंप

संवाददाता—संतकबीरनगर। राप्ती नदी खतरे के निशान से 32 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। वहीं सरयू नदी स्थिर है, लेकिन नदी और तटबंध के बीच बसे 32 गांव के लोग सहमे हैं। इसी बीच रामपुर—मखदुमपुर तटबंध पर बने रेगुलेटर से पानी का रिसाव होने लगा, जिसकी सूचना पर हड़कंप मच गया। बाढ़ खंड के अधिकारी पहुंचे और घंटों मशक्कत के बाद उसे ठीक कराए। नदियों के जलस्तर को देखते हुए अधिकारी तटबंध पर डेरा जमाए हुए हैं। साथ ही स्वास्थ्य, पशुपालन, पंचायती राज समेत अन्य विभागों को सतर्क कर दिया गया है। करमैनी—बेलौली तटबंध पर राप्ती का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। चौथे दिन राप्ती का जलस्तर 79.18 मीटर पर पहुंच गया। ऐसे में राप्ती लाल निशान से महज 32 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। विभागीय अधिकारियों का दावा है कि जलस्तर बढ़ने के बाद भी बांध पर जलस्तर का ना तो कोई दबाव है न ही तटबंध को कोई खतरा है। तटबंध पूरी तरह सुरक्षित है। सहायक अभियंता राम उजागर लाल के नेतृत्व में चार अवर अभियंता समेत अन्य कर्मचारी तटबंध और जलस्तर की निगरानी में लगे हैं। कटान व रेनकट मुक्त तटबंध को रखने के लिए ड्रेनेज खंड द्वितीय द्वारा तटबंध पर जगह—जगह मिट्टी इकट्ठा किए गए हैं। बेलौली और नौगो में तटबंध से जलस्तर सट रहा है लेकिन जलस्तर का दबाव बांध पर नहीं है। अधिकारियों की टीम 19.2 किलोमीटर तटबंध की जहां निगरानी कर रही है। सहायक अभियंता का कहना है कि तटबंध पर सभी रेनकट भरे जा चुके हैं। जलस्तर बढ़ रहा है लेकिन नदी के पानी का दबाव करमैनी—बेलौली तटबंध पर कहीं से नहीं है। तटबंध पूरी तरह सुरक्षित है। जलस्तर तथा तटबंध की लगातार निगरानी कराई जा रही है। आवश्यकता अनुसार बाढ़ निरोधक कार्य कराए जा रहे हैं। वही धनघटा में सरयू नदी का जलस्तर भले ही स्थिर हो रहा। लेकिन बाढ़ का पानी नदी और एमबीडी बांध के बीच फैलते हुए कई गांव को घेरने में लगा है। वहीं रामपुर मखदुमपुर बांध पर रामपुर के पास लगे रेगुलेटर सुबह रिसाव होने लगा। जिसकी सूचना पर पहुंचे अधिकारियों ने तीन घंटे मशक्कत के बाद उसे सही किया।

नदी का जलस्तर सुबह खतरे के निशान से महज 40 सेंटीमीटर नीचे रह गया है। शाम को नदी का पानी स्थिर तो जरूर हुआ लेकिन दियारा क्षेत्र में बाढ़ का पानी फैल चुका है। जिससे बाढ़ के पानी से गायघाट दक्षिणी, दौलतपुर, खालेपुरवा, ढोलबजा, गुनवतिया, चकदहा, सियर कला, नारायनपुर आदि गांव बाढ़ के पानी से घिरने लगे हैं। गायघाट दक्षिणी के प्रधान बालेंद्र उर्फ पप्पू ने बताया कि बाढ़ से जहां फसलें जलमग्न हो गई हैं। वही गांव के करीब पानी पहुंचने से गांव के रास्ते अवरूद्ध होने लगे हैं। प्रधान का कहना है कि अभी कहीं पर नाव की जरूरत नहीं है। लेकिन पानी इसी तरह बढ़ा तो दो दिन के अंदर नाव की आवश्यकता पड़ जाएगी।

आरटीई के तहत बच्चों को प्रवेश नहीं देना चाहते प्राइवेट स्कूल

संवाददाता—सिद्धार्थनगर। शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) से आगे कुछ स्कूलों अपनी मनमानी चल रही है। आरटीई के नियमों के तहत लाटरी में नाम आने के बाद भी उनको प्रवेश के लिए पब्लिक स्कूल संचालक परेशान कर रहे हैं। आधार समेत अन्य जरूरी प्रपत्र लगे होने के बावजूद भी परेशान करने की नीयत से खामियां निकालकर प्रवेश के लिए टहला रहे हैं। शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) अंतर्गत गरीब परिवार के बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा का प्राविधान है। इसके तहत लाटरी निकलती है। इसके आधार पर संबंधित स्कूलों में अभिभावकों को प्रवेश कराने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस बीच अभिभावक जब स्कूल में प्रवेश कराने के लिए पहुंचते हैं उस समय स्कूल प्रबंधन की ओर से प्रपत्र के नाम पर परेशान किया जाता है। जिस वार्ड या ग्राम पंचायत में स्कूल है उसी में आइटीई में प्रवेश का पात्र बच्चे के अभिभावक रहते हैं या नहीं इसके लिए सभासद या ग्राम प्रधान का पत्र मांगा जा रहा है। अभिभावक उनके घर चक्कर काट रहे हैं। विभागीय अधिकारियों की मानें तो आरटीई में लाटरी तभी निकलती है जब प्रपत्र सही होते हैं। इसके अलावा भी पार्षदों से लिखवाने के नाम पर कुछ स्कूल परेशान कर रहे हैं। ऐसे में कुछ शिकायतें अब तक प्राप्त हुई हैं। आरटीई के तहत 25 फीसदी बच्चों का दाखिला लेना पब्लिक स्कूलों में अनिवार्य है।

कक्षा एक में आरटीई में गरीब परिवार, दिव्यांग, कैंसर पीड़ित माता या पिता के बच्चों का निःशुल्क प्रवेश आरटीई लेने का नियम है। अभिभावक उसी वार्ड का रहने वाला हो, जिस वार्ड में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। लाटरी से प्रवेश मिलने पर आठवीं तक निशुल्क पढ़ाई बच्चे स्कूल में करते हैं। जिला समन्वयक अमित शुक्ल ने बताया कि शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के तहत जिले में चार चरणों में निकले लाटरी के तहत लक्ष्य 1569 के सापेक्ष 1302 बच्चों को पूरे जिले में अलग—अलग निजी स्कूलों में प्रवेश कराने की पहल की गई। प्रथम चरण में 114 के सापेक्ष 96, द्वितीय चरण में 675 के सापेक्ष 545, तृतीय चरण में 565 के सापेक्ष 460, चतुर्थ चरण में 215 के सापेक्ष 201 बच्चों का प्रवेश के लिए लाटरी निकली है।

देवेंद्र कुमार पांडेय, बीएसए ने कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के तहत चार चरणों में जिलाधिकारी के निर्देशन में इस सत्र में 1302 बच्चों की लाटरी निकली है। सभी को संबंधित स्कूलों में प्रवेश के लिए कहा गया है। चयनित स्कूलों की ओर से प्रवेश न करने की शिकायत मिली तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

31 जुलाई तक अपनी फसलों का बीमा कराएं किसान

संवाददाता—गोरखपुर। खरीफ की फसल के बीमा के लिए 31 जुलाई की तिथि निर्धारित की गई है। जिंसवार प्रीमियम की दरें निर्धारित की गईं हैं। केसीसी धारक किसानों (ऋणि किसान) के खाते से प्रीमियम की रकम काट दी जाएगी। जो किसान इसका लाभ लेने के इच्छुक नहीं है, उनको 7 दिन पूर्व सूचना बैंक को देनी होगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले में रबी व खरीफ सीजन में किसानों का प्रीमियम काटा जाता है। खरीफ का सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में 31 जुलाई तक किसान इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। बीमा कंपनी द्वारा फसल बार प्रीमियम की दरें निर्धारित कर दी गई है। जिन किसानों के केसीसी बने हैं उनके खाते से प्रीमियम की रकम काट ली जाएगी। केसीसी धारक ऐसे किसान जो बीमा कराने के इच्छुक नहीं है, उनका अंतिम तिथि यानी 31 जुलाई के सात दिन पूर्व लिखित में सूचना बैंक में देनी होगी, अन्यथा उनका प्रीमियम काट दिया जाएगा। ऐसे किसान जो केसीसी कार्डधारक नहीं है वह जन सुविधा केंद्रों के माध्यम से अपना प्रीमियम जमा कर सकते हैं जिससे उनकी फसल बीमित हो जाएगी और नुकसान की स्थिति में ऐसे किसानों को क्षतिपूर्ति दी जाएगी। उप कृषि निदेशक डॉ अरविंद सिंह ने किसानों से अपील किया है कि वह योजना का लाभ उठाने के लिए समय से अपना प्रीमियम कटवाएं जिससे फसल नुकसान होने की स्थिति में उनको क्षतिपूर्ति का लाभ मिल सके।

जिला कृषि अधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि गोरखपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार की बीमा कम्पनी, एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिलेड नामित है। खरीफ 2024 में धान, मक्का, मूंगफली व अरहर फसल बीमा किया जा रहा है। किसान भाई कामन सर्विस सेन्टर के माध्यम से अपने फसल का बीमा करा सकते हैं। योजना का लाभ बटाईदार किसान भी उठा सकते हैं। उन्हें केवल एक प्रमाण पत्र देना होता है जिसमे उनके भूस्वामी द्वारा यह प्रमाणित करना होता है कि इस जमीन का सम्पूर्ण लाभ उन्हें न दे करके उनके बटाईदार को दिया जाय।

फसल बीमा का लाभ लेने के लिए गैर ऋणी किसानों को बचत बैंक खाता का नवीनीकरण पासबुक, मोबाइल नम्बर, आधार कार्ड, जमीन की खतौनी। जानकारी के लिए फसल बीमा कम्पनी के टोल फ्री 14447 अथवा प्रबंधक रंजीत सिंह के मोबाइल नम्बर 8353930425 और आलोक गुप्ता के मोबाइल नम्बर पर 7518207819 पर काल कर अधिक जानकारी ले सकते हैं।

पांच लाख पशुओं को लगेगा एफएमडी का टीका

संवाददाता—अम्बेडकरनगर। पशुपालन विभाग की तरफ से पांच लाख से अधिक पशुओं को एफएमडी का टीका लगेगा। बारिश के दौरान पशुओं में खुरपका व मुंहपका जैसी जानलेवा बीमारी का संक्रमण होता है। इस बीमारी से बचाव के लिए विभागीय स्तर से तैयारी शुरू कर दी गई है। खुरपका व मुंहपका जैसी जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए विभागीय स्तर से आगामी 15 जुलाई से अभियान चलेगा। अभियान में साढ़ पांच लाख पशुओं को टीका लगाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए कुल 23 टीमें गठित की गई हैं। इसके साथ ही छरू एम्बुलेंस को भी अलर्ट कर दिया गया है। इन्हें इमरजेंसी में प्रयोग किया जा सकेगा। बरसात के मौसम में पशुओं में खुरपका व मुंहपका जैसी जानलेवा बीमारी होने की अधिक संभावना रहती है।

इसे देखते हुए स्वास्थ्य निदेशालय के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। 31 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान को सफल बनाने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं।

तीन सदस्यीय इस टीम में पशुधन प्रसार अधिकारी, पैरावेट व वैक्सीनेटर शामिल रहेंगे।

राहुल मद्देशिया अपहरण प्रकरण में पूर्व मंत्री अमरमणि की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

संवाददाता–बस्ती। राहुल मद्देशिया के अपहरण के मामले में भगोड़ा घोषित पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। एमपी–एमएलए कोर्ट ने तीन जुलाई को डाली गई अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अमरमणि त्रिपाठी के वकील ने तीन जुलाई 2024 को अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। जमानत अर्जी में वकील ने लिखा था, अमरमणि को परेशान करने के लिए फंसाया गया है। वह एफआईआर में नामजद अभियुक्त नहीं है। विवेचना में अन्य के साथ सहअभियुक्त में नाम बढ़ा दिया गया है। इस मामले में 19 दिसम्बर 2001 को लखनऊ में उनकी गिरफ्तारी हुई। ट्रांजिट रिमांड पर बस्ती न्यायालय में 21 दिसम्बर 2001 को पेश किया गया था। वकील ने लिखा था कि एक फरवरी 2002 को जमानत पर रिहा होने का आदेश हुआ था। दूसरे केस में वह 20 वर्षो तक कारागार में निरुद्ध थे। इस समय भी वह बीमार चल रहे हैं और डॉक्टर की निगरानी में हैं। मुकदमे के वादी की मृत्यु हो चुकी है। राहुल ने स्वयं सुलहनामा दाखिल किया है कि अपहरण में अमरमणि की कोई भूमिका नहीं है। प्रार्थी के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट न्यायालय से जारी है। गिरफ्तार होने की आशंका है। इसलिए अग्रिम जमानत पर रिहा करने की कोर्ट से अपील है। कोर्ट ने वकील की दलीलों को सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित कर लिया था। गुरुवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। में दो और संपत्तियां मिलने की बात सामने आई। इन संपत्तियों की कुर्की के लिए पुलिस ने कमिश्नरेट लखनऊ के एसडीएम से पत्राचार किया है। इसका हलफनामा विशेष न्यायाधीश एमपी–एमएलए कोर्ट में दिया है। विशेष न्यायाधीश एमपी–एमएलए, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम प्रमोद कुमार गिरि की अदालत में सुनवाई के दौरान बस्ती पुलिस ने हलफनामा दिया है। कहा है कि अमरमणि की लखनऊ स्थिति संपत्तियों की कुर्की के लिए पत्राचार किया गया है।

टापू बने गांव, राप्ती नदी ने पार किया खतरे का निशान

संवाददाता–गोरखपुर। नदियों के बढ़ रहे जलस्तर के बीच प्रशासन ने छह गांवों को बाढ़ प्रभावित मान लिया है। इनमें सदर तहसील के चार, सहजनवां और गोला का एक–एक गांव शामिल है। बड़हलगंज क्षेत्र के 20 से ज्यादा गांव पानी से घिर गए हैं तो सहजनवां क्षेत्र में आमी के पानी में 50 एकड़ से ज्यादा फसल डूब गई है। कैंपियरगंज में भी समस्या बढ़ रही है। गुरुवार सुबह राप्ती नदी ने खतरे का निशान पार कर लिया है। शाम चार बजे राप्ती खतरे के निशान से 11 सेंटीमीटर ऊपर बह रही थी। नदी में बढ़त जारी थी। हालांकि राहत की बात यह है कि सरयू नदी का पानी अयोध्या पुल पर खतरे के निशान से 32 सेंटीमीटर ऊपर जाने के बाद घटने लगा है। सहजनवां संवाददाता के अनुसार सहजनवां ब्लाक के दो गांवों के मैरूंड होने के साथ ही पिपरौली में भी आमी का कहर बरपा है। ब्लाक के आधा दर्जन गांवों में करीब 50 एकड़ क्षेत्रफल में सब्जी की खेती डूब गई है। बरहुआं के पास राप्ती का कटान जारी है। एसडीएम दीपक कुमार गुप्ता ने मैरूंड गांव गहिरा का निरीक्षण कर लाइफ सपोर्ट जैकेट का वितरण किया। कैली के नेबूलाल ने बताया कि दो बीघा मक्का डूब गया है। आमी का पानी गांवों की तरफ बढ़ने लगा है। यही हाल रहा तो दो से तीन दिन में ब्लाक के कुछ और गांव मैरूंड हो सकते हैं। बोक्टा बरवार बांध पर बरहुआं गांव के सामने जारी कटान फिलहाल रुकता नहीं दिख रहा है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग की टीम न जाने पर लोगों में नाराजगी है। कैंपियरगंज क्षेत्र के बहबोलिया–रिगौली और खजूरगांवा –मिरिहिरिया के बीच के सिवान में लगभग पचास एकड़ धान की फसल जलमग्न हो गई है। मिरिहिरिया के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि भवानी शंकर पांडेय, डोरा सिंह, प्रमोद पांडेय ने बताया कि मिरिहिरिया और बहबोलिया गांव के पास बंधे के पुलिया से पानी का रिसाव हो रहा है। रिगौली ग्राम प्रधान जोगिंदर निषाद, वीरेंद्र निषाद आदि ने बताया कि भरवलिया बंधे के पुलिया के रास्ते पानी आने से भरवलिया–भैसला सिवान की फसल डूबने का खतरा बना हुआ है। राप्ती व आमी नदी का पानी कुसमौल–बांसगांव सड़क के दोनों तरफ फैल गया है। कुसमौल, भुसवल, जूड़ापुर, डेफरा, रेहरा, महाडीह, हाटा, चंदौली, विश्रामपुर आदि गांवों में आवागमन प्रभावित हो रहा है। बाढ़ के पानी से ताल नगरी, ताल ढेलहरा, अमियार, कुसमौल व बांसगांव में धान, मक्का व सब्जी की खेती डूब गई है। बड़हलगंज विकास खंड के कछारांचल में सरयू व राप्ती नदियों की बढ़त जारी है।

जनसंख्या दिवस पर संगोष्ठी में विमर्श

पर्यावरण रक्षा के लिये लगाये पौध

संवाददाता–बस्ती। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर रोटरी क्लब बस्ती सेंट्रल द्वारा दिल्ली सीनियर पब्लिक स्कूल पचपेडिया रोड निकट अर्चना हॉस्पिटल पर बढ़ती जनसंख्या के कारण 'पर्यावरण पर होने वाले कुप्रभाव' विषयक गोष्ठी के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में विश्व जनसंख्या 2024 की थीम 'किसी को पीछे ना छोड़े, सब की गिनती करें' विषय पर भी विस्तार से चर्चा हुई।

स्कूल की छात्रा स्तुति गुप्ता, समृद्धि तिवारी ने कहा कि पर्यावरण को संरक्षित न करने के कारण बढ़ती गर्मी, अचानक मौसम में परिवर्तन कई तरह के प्रभाव पड़ते हैं। सोनाक्षी पाण्डे, समृद्धि तिवारी, श्वेता चौधरी, आयुष, आर्य, संकल्प चौधरी आदि बच्चों द्वारा हरे पेड़ों को ना काटने, पेड़ों को संरक्षित करके विषय पर नाटक का मंचन किया गया।

सचिव एल.के. पाण्डेय ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या के कारण स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, रोजगार कई क्षेत्रों में प्रगति के बाद भी सभी लोगों को सुविधाा नहीं मिल रही है। बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण के लिए एक समस्या बन गई है। शहरों में बढ़ती हुई जनसंख्या के फलस्वरूप तंग मलिन बस्तियों का जाल बिछता जा रहा है। इससे पेय जल, भोजन, रोजगार के निपटारे आदि की समस्याएं बढ़ रही हैं।

कार्यक्रम संयोजक रोटेरियन अमरमणि पाण्डेय ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को जन्मदिन विवाह या किसी अन्य अवसरों पर पेड़ जरूर लगाने चाहिये। समय पर वर्षा का न होना, भयंकर बाढ़, भूकंप, महामारी आदि प्राकृतिक आपदाओं का कारण पर्यावरण का प्रदूषित हो जाना है। इससे मनुष्य में अनेक प्रकार की बीमारियां फैल रही है। हम सभी को अपने विशेष अवसरों पर पौधा रोपण जरूर शुरू करना चाहिए जिससे हम आने वाले भारत को बेहतर पर्यावरण दे सकें।

इस अवसर पर आम, नीम, आंवला, अशोक, हरसिंगार आदि पौधों का बच्चों के साथ पौधारोपण किया गया। साथ ही इन पौधों की जिम्मेदारी बच्चों को दी गई।

क्लब अध्यक्ष रोटेरियन वार्मिक मिराज ने कहा की क्लब के द्वारा जनहित एवं सामाजिक कई कार्य किए जा रहे हैं जो निरंतर जारी रहेंगे।

इस अवसर पर अर्चना हॉस्पिटल की डायरेक्टर श्रीमती अर्चना पाण्डेय, रोटेरियन दिलीप कुमार गुप्ता, डॉक्टर कलीमुल्लाह, आशीष वाधवानी, सेवा ब्लड केंद्र के डायरेक्टर रोटेरियन मनीष सिंह, सैनिक चंद्र भूषण सिंह, चार्ट अध्यक्ष रोटेरियन मुनीरुद्दीन अहमद,शिक्षक दिव्या पाठक, नीलम चौधरी, लक्ष्मी वर्मा, अविनाश, प्रिया शुक्ला, राम आशीष, रिया सिंह तथा अनेक छात्र–छात्राएं उपस्थित रहे।

ओपीडी पर्ची की नई व्यवस्था ने खड़ी की मरीजों के लिए दुश्वारियां

संवाददाता–संतकबीरनगर। जिला अस्पताल में ऑनलाइन ओपीडी पर्ची कटवाने की नई व्यवस्था मरीजों के लिए दुश्वारियां खड़ी कर रही है। नई व्यवस्था में जिन लोगों के पास बड़ी मोबाइल नहीं है उनकी पर्ची ही नहीं बन रही है। उन्हें बिना उपचार के वापस जाना पड़ रहा है। पर्ची काउंटर पर मरीजों से यही कहा जा रहा कि बड़ी मोबाइल लेकर आइए आनलाइन पर्ची ले जाइए। यह पर्ची नहीं मिलने से दर्जनों बीमार लोग निजी अस्पताल में इलाज कराने को मजबूर हुए या फिर वे निराश होकर घर चले गए।

शासन के निर्देश पर अब मरीजों को ओपीडी पर्ची ऑनलाइन मिल रही है। जिससे कि अस्पताल में आने वाले मरीजों का डाटा फीड रहे। इस पर्ची से मरीज को पर्ची के लिए भाग दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। चिकित्सक के पास सभी जानकारी ओपीडी रजिस्ट्रेशन नंबर डालते ही हो जाएगी। यदि संबंधित मरीज को हायर सेंटर रेफर भी किया जा रहा है तो वहां पर केवल रजिस्ट्रेशन नंबर ही डालने की जरूरत होगी। उसके बाद मरीज का डाटा आते ही उपचार चालू हो जाएगा। इस व्यवस्था के लिए आभा पोर्टल से भी पर्ची काटी जा रही है। बदन दर्द से परेशान बघुआ गांव निवासी राम कुमार ने ओपीडी पर्ची के लिए काउंटर पर खड़े रहे। काउंटर पर बैठे कर्मी ने बताया कि बिना बड़ी मोबाइल के ऑनलाइन पर्ची नहीं मिल पाएगी। उन्होंने कहा कि साहब हमारे पास तो छोटी मोबाइल है। अब बड़ी मोबाइल कहां से ले लाऊं। इसके बाद वह मेडिकल स्टोर से दवा लेकर घर चले गए।

चोरों के गैंग के एक आरोपी को 9 माह का सश्रम कारावास

संवाददाता–संतकबीरनगर। चोरों के गैंग के एक आरोपी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल कुमार एकादश की कोर्ट ने नौ माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी सचिन पर सजा के साथ एक हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है।

अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को दस दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। आरोपी को चोरी की योजना बनाते समय गैंग के सदस्यों के साथ गिरफ्तार किया गया था। मामला जिले कोतवाली खलीलाबाद थाना क्षेत्र के ओसवाल डालडा फैक्ट्री के पास का है।

ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी अजीत कुमार सिंह ने बताया कि प्रकरण में उप निरीक्षक अरविन्द कुमार यादव ने अभियोग पंजीकृत कराया था। वादी का आरोप है कि 28 दिसम्बर 2023 को क्षेत्र भ्रमण पर थे। ओसवाल डालडा फैक्ट्री के पास तीन चोरों को चोरी की योजना बनाते समय गिरफ्तार किया गया था।

इनमें से एक सचिन पुत्र रामचरन मोहल्ला बरईटोला थाना कोतवाली खलीलाबाद का रहने वाला है। आरोपियों के पास से नकब लगाने के दो सब्बल, एक पेचकश और दो चाकू बरामद हुआ था। पुलिस ने विवेचना के पश्चात आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। सीजेएम अनिल कुमार एकादश की कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात आरोपी को दोष सिद्ध करार देते हुए नौ माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

16 सड़कों के लिए मिला 10 करोड़ का बजट

संवाददाता–बस्ती। लोक निर्माण विभाग को मंडल के 16 चालू कार्यो पर काम के लिए शासन से 10 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। विभिन्न मार्गो पर इस बजट से काम कराया जाना है। आरआईडीएफ योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–56 के अंतर्गत यह बजट जारी किया गया है। मंडल के तीनों जिलों में सर्वाधिक सिद्धार्थनगर के 12 व बस्ती और संतकबीरनगर के दो–दो प्रोजेक्ट के लिए धन स्वीकृत किया गया है। धन मिलने के बाद इस पर जल्द काम शुरू हो जाएगा।

शासन की ओर से जो कार्य स्वीकृत किए गए हैं उनमें सिद्धार्थनगर में रीवा नानकार सम्पर्क मार्ग से लच्छनपुर घुसवा सम्पर्क मार्ग, इंडोनेपाल बार्डर से रघुनाथपुर सम्पर्क मार्ग, एलडी किलोमीटर चार दुल्हा दरम्यानी मार्ग से लक्ष्मीजोत, भजनजोत होते हुए नरायनपुर सम्पर्क मार्ग, अलीगढ़वा ताल मझौली सम्पर्क मार्ग से बनकटवा सम्पर्क मार्ग, धोबहा बांकी सम्पर्क मार्ग से बांकी बलगवा सम्पर्क मार्ग, जोगिया नादेवर से दत्तपुर होते हुए बकुरहवा सम्पर्क मार्ग, ककरही सम्पर्क मार्ग से महापरूआ सम्पर्क मार्ग, पीएमजीएसवाई निबियहवा सम्पर्क मार्ग से तुलसीपुर होते हुए मल्लाडीह सम्पर्क मार्ग, ककरही टड़िया गायघाट मार्ग के किमी–9 से पचपेड़वा सम्पर्क मार्ग, सोहास लोटन से पोखर भिटवा होते हुए छोट पोखरभिटवा सम्पर्क मार्ग, बनियाडीह कोल्हुआ सम्पर्क मार्ग, उसका सोहास मोहाना मार्ग के बलूरी चौराहे से गोवर्धनपुर सम्पर्क मार्ग,

बस्ती में भिटहा से बेलराई सेमरा डड़वा लगुनी जूनियर हाईस्कूल तक मार्ग, बस्ती महसो महुली पगार गांव से जोगिया जयपुर तक नहर पटरी होते हुए सम्पर्क मार्ग, संतकबीरनगर में धायपोखर से केवटली मानपुर होते हुए अजाव सम्पर्क मार्ग, बीएमटीसी से महुआर होते हुए सुटेहा सम्पर्क मार्ग शामिल है।

17 चिकित्साधिकारी बर्खास्त

लखनऊ (आभा)। बिना सूचना ड्यूटी से लंबे समय तक गैरहाजिर रहने वाले विभिन्न जिलों के 17 चिकित्साधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इन चिकित्साधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को दिए थे। साथ ही तीन चिकित्साधिकारियों पर अनुशासनिक कार्रवाई भी की गई है। डिप्टी सीएम का कहना है कि चिकित्सकीय सेवाओं में लापरवाही बरतने वाले किसी भी चिकित्सक या स्वास्थ्यकर्मी को बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किए जाने के लिए सेवाओं में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। लापरवाह स्वास्थ्यकर्मियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को लंबे समय से चिकित्सकीय सेवाओं से गैरहाजिर रहने वाले 17 चिकित्सकों को ड्यूटी से बर्खास्त कर दिया गया है। इनमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बल्देव, मथुरा के चिकित्साधिकारी डा. आनंद गोयल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सब सेंटर मोहनकोला, सिद्धार्थनगर की चिकित्साधिकारी डा. नेहा सिंह, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जगदीशपुर बस्ती की चिकित्साधिकारी डा. निक्की,

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जमीन फरेंदा आजमगढ़ की चिकित्साधिकारी डा. ईशा सिंह, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेसरहा शामिल हैं।

इसके अलावा सिद्धार्थनगर की चिकित्साधिकारी डा. पारुल वर्मा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होलीपुरा, बाह आगरा की चिकित्साधिकारी डा. कृतिका, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अहारन, आगरा की चिकित्साधिकारी डा. सुनाक्षी सेठ, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सब सेंटर बेतिया, सिद्धार्थनगर के चिकित्साधिकारी डा. रजनीश चौधरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुरली छपरा, बलिया के चिकित्साधिकारी डा. राहुल कुमार, अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी बलिया डा. जैन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालपी, जालौन के चिकित्साधिकारी डा. सत्येंद्र पुरवार, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बमटापुर (बरनाहाल) को बर्खास्त किया गया है।

मैनपुरी की चिकित्साधिकारी डा. अंजली वर्मा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औछा, मैनपुरी की चिकित्साधिकारी डा. स्वाति कुशवाहा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मड़िहान, मिर्जापुर के चिकित्साधिकारी डा. अखलाक अहमद, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भोजीपुरा, बरेली की चिकित्साधिकारी डा. रूबी जायसवाल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसराना फिरोजाबाद की चिकित्साधिकारी डा. सरिता पांडेय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हथौली जयसिंहपुर, फिरोजाबाद के चिकित्साधिकारी डा. मनीष मगन पर कार्रवाई की गई है। तीन चिकित्सकों पर अनुशासनिक कार्रवाई के निर्देश भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिए हैं। मंडलीय अपर निदेशकों को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। इनमें जिला चिकित्सालय, झांसी के अस्थि रोग विशेषज्ञ डा. मुकुल मिश्रा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुर, बाराबंकी में तैनान नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. माधवी सिंह एवं मुख्य चिकित्साधिकारी, बरेली के अधीन डा. प्रमोद कुमार शामिल हैं।

बाढ़ कार्यों में लापरवाही पर दस अफसरों से जवाब तलब, बड़ी कार्रवाई की तैयारी

लखनऊ (आभा)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बाढ़ संबंधी कार्यों में लापरवाही और खराब हुईं फसलों के सर्वे में लापरवाही बरतने वाले पांच जिलों के एडीएम एफआर और आपदा विशेषज्ञों से स्पष्टीकरण तलब किया है। इन पांचों जिलों के लापरवाह अधिकारियों को दो दिन में अपना स्पष्टीकरण देना होगा। बताया जा रहा है कि अगर जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो सीएम योगी सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। राहत आयुक्त जीएस नवीन ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित इलाकों की रोजाना अपडेट ले रहे हैं। साथ ही अधिकारियों को राहत कार्यों से संबंधित दिशा–निर्देश दे रहे हैं ताकि जनहानि–धनहानि को कम से कम किया जा सके।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लखनऊ, प्रतापगढ़, सीतापुर, अंबेडकरनगर और बलिया के एडीएम एफआर और आपदा विशेषज्ञ द्वारा बाढ़ संबंधी सूचना ससमय उपलब्ध न कराने एवं क्षतिग्रस्त फसलों के सर्वे में लापरवाही की सूचना मिली। इस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए लापरवाह पांचों जिलों के एडीएम एफआर और आपदा विशेषज्ञ को स्पष्टीकरण सौंपने के निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने इन सभी को दो दिन में स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।

राहत आयुक्त ने बताया कि सीएम योगी के निर्देश पर लखनऊ के एडीएम एफआर राकेश सिंह, आपदा विशेषज्ञ अमर सिंह, प्रतापगढ़ के एडीएम एफआर त्रिभुवन विश्वकर्मा, आपदा विशेषज्ञ अनुपम शेखर तिवारी, अंबेडकरनगर के एडीएम एफआर सदानंद गुप्ता, आपदा विशेषज्ञ सूर्यभान सिंह को नोटिस जारी की गयी है। इसके अलावा बाढ़ संबंधी कार्यों में शिथिलता बरतने पर सीतापुर के एडीएम एफआर नितीश कुमार सिंह, आपदा विशेषज्ञ हीरालाल और बलिया के एडीएम एफआर देवेंद्र प्रताप सिंह, आपदा विशेषज्ञ पियुष कुमार सिंह को नोटिस जारी की गयी है।

राहत आयुक्त ने बताया कि सभी पांच जिलों के एडीएम एफआर और आपदा विशेषज्ञों को दो दिन में अपना जवाब देना होगा। इसके बाद उनके जवाब को मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा जाएगा। जानकारों की मानें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर लापरवाह अधिकारियों के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

आशा कार्यकत्रियों ने सौंपा ज्ञापनः महत्वपूर्ण कार्यों के लिये भुगतान की मांग

संवाददाता–बस्ती । गुरुवार को आल इण्डिया आशा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सन्तोष पाण्डेय के नेतृत्व में आशा कार्यकत्रियों ने जिलाधिकारी के प्रशासनिक अधिकारी और मुख्य चिकित्साधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मांग किया कि दस्तक अभियान, संचारी रोग नियंत्रण अभियान 'डाट', टी.वी. खोज अभियान, डायरिया नियंत्रण, बाल स्वास्थ्य पोषण माह, आयुष्मान कार्ड जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के बदले उन्हें भुगतान दिलाया जाय। ज्ञापन देने के बाद मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सन्तोष पाण्डेय ने बताया कि आशाओं को कोई वेतन, मानदेय नहीं दिया जाता है केवल कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि ही दी जाती है। वो कब और कितना मिलना है कोई पता नहीं रहता। प्रोत्साहन राशि देने में भी मनमानी की जाती है। दस्तक अभियान, संचारी रोग नियंत्रण अभियान, (डाट) टीवी खोज अभियान, डायरिया नियंत्रण, बाल स्वास्थ्य पोषण माह, आईडी और आयुष्मान कार्ड निःशुल्क करायें जाते है और इसका किसी भी प्रकार का कोई भुगतान देय नहीं होता। सरकार द्वारा निर्धारित मनरेगा मजदूरी भी 237 रु. है जो कि एक अनट्रेंड लेवर होते हैं। तो क्या प्रशिक्षण लेकर समाज को स्वस्थ रखने वाली आशा इसकी भी हकदार नहीं हैं।

दस्तक एवं संचारी अभियान 11 जुलाई से प्रारंभ होकर 31 जुलाई तक चलेगा यानी 21 दिन आशाओं को बिना पैसे के कार्य करना है। आशा कार्य से पीछे नहीं है लेकिन उनको कार्य का पारिश्रमिक मिलना चाहिए। एक सप्ताह के अंदर दस्तक एवं संचारी अभियान आभा, आयुष्मान जैसे फ्री करायें जाने वाले कार्यों पर सरकार भुगतान पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें तभी दस्तक एवं संचारी जैसे कार्य होंगे

अन्यथा आशाये कार्य नहीं करेंगी। कार्य न होने पर सरकार स्वयं जिम्मेदार होगी। कहा कि एक तरफ भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार महिला कल्याण पर अच्छा खासा बजट खर्च कर उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बना रही है और दूसरी तरफ हम महिला श्रमिकों को काम का दाम भी नहीं मिल रहा है। ये कौन सा महिला सशक्तिकरण है। ये हम लोगों के साथ कौन सा न्याय है। ज्ञापन देने वालों में राष्ट्रीय महासचिव शैलेन्द्री श्रीवास्तवा, उपाध्यक्ष अनुसुईया तिवारी, किरन मिश्रा, सिया बारी, अर्चना ओझा, नीर सिंह, विजय लक्ष्मी, उमा सिंह, नीतू सिंह, आकंक्षी पाण्डेय, उमा सिंह, रेखा, सुशीला, कृष्णावती, शीलू सिंह, दीपिका, बबिता, सावित्री देवी, स्नेह लता माया देवी ज्ञानमती मीना देवी शर्मिला देवी सीमा देवी विमला दुबे, सोनम सिंह, गीता सिंह, संगीतादेवी, राधिका देवी, अमरावती, सविता सिंह, मालती पण्डिय, चन्द्रावती, पूनम, इसरावती चौधरी, दीपमाला, पूनम सिंह, कैसरजहां, शारदा, रेखा, निर्मला तिवारी के साथ ही बड़ी संख्य में आशा कार्यकत्रियां शामिल रहीं।

मंत्री ओपी राजभर ने बेदी राम समेत अपने ही चार विधायकों को बता दिया सपाई

लखनऊ (आभा)। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओपी राजभर ने अपने ही छह में से चार विधायकों को समाजवादी पार्टी का नेता बता दिया है। अपनी पार्टी के विधायक बेदी राम के पेपर लीक मामले में फंसने और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने पर ओपी राजभर ने यहां तक कह दिया कि उनके चार विधायक असल में समाजवादी पार्टी से भेजे गए लोग हैं। उन्होंने विधायक बेदी राम, विधायक जगदीश नारायण, विधायक अब्बास अंसारी और विधायक दूधराम को अखिलेश यादव की तरफ से भेजे गए प्रत्याशी बताया। ओपी राजभर की पार्टी से यूपी में कुल छह विधायक हैं।

एक चैनल से बातचीत में ओपी राजभर ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान सुभासपा और सपा का गठबंधन हुआ था। इसमें सुभासपा को 17 सीटें दी गई थीं। कहा गया था कि 14 सीटों पर सपा के लोग चुनाव लड़ेंगे। इन्हें सुभासपा केवल सिंबल देगी, यही हुआ। सुभासपा ने केवल तीन सीटों संडीला, शिवपुर और जहूराबाद में अपने प्रत्याशी खड़े किए थे। संडीला में प्रदेश अध्यक्ष, शिवपुर में महासचिव और जहूराबाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी मैं चुनाव मैदान में उतरा था। इसके अलावा अन्य सीटों पर सपा के प्रत्याशी थे।

राजभर ने कहा कि जौनपुर से विधायक जगदीश नारायण राय भले ही मेरी पार्टी से विधायक हैं लेकिन समाजवादी पार्टी की रसीद काट रहे हैं, गाड़ी पर सपा का झंडा और सपा की टोपी लगाकर घूम रहे हैं। इसी तरह मऊ में अब्बास अंसारी भी समाजवादी पार्टी से ही भेजे गए प्रत्याशी हैं।

लापरवाही के आरोप में नगर आयुक्त ने किया दो ड्राइवरों को बर्खास्त

संवाददाता–गोरखपुर। महापौर डॉ मंगलेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जोन 07 और 08 में साफ सफाई और डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के कार्यो की समीक्षा बैठक में बड़ी कार्रवाई हुई। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने वार्ड संख्या 27 से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करने वाले आउटसोर्सिंग के 02 वाहन चालकों को बर्खास्त कर दिया। वहीं, वार्ड संख्या 74 से मेट एवं सुपरवाइजर को दूसरे वार्ड में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। नगर आयुक्त सभागार में हुई बैठक में अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्र, जोन 07–08 के जोनल अधिकारी, समस्त सफाई निरीक्षक, समस्त सुपरवाइजर, सभी पार्षद एवं डोर टू डोर गाड़ियों के वाहन चालक मौजूद रहे। सभी वाहन चालकों को क्यूआर कोड के माध्यम से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन और यूजर चार्ज की नियमित वसूली करने के निर्देश दिए गए। बैठक में कार्य में लापरवाही करने पर वार्ड संख्या 27 के 02 ड्राइवर अफजल और आकाश यादव को नगर निगम की सेवा से हटा दिया। वार्ड संख्या 74 में तैनात आउटसोर्सिंग के मेट एवं सुपरवाइजर को दूसरे वार्ड में तैनात करने के निर्देश दिए।

प्रशिक्षण में विभिन्न योजनाओं की दी जायेगी जानकारी

संवाददाता–संतकबीरनगर। संतकबीरनगर जिले में उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज एसोसिएशन नव उद्यमियों को प्रशिक्षण देकर जागरूक करेगा। सरकार की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। कार्यक्रम का आयोजन 16 जुलाई को औद्योगिक क्षेत्र खलीलाबाद स्थित एसोसिएशन के कार्यालय में होगा। उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद पाठक ने कहा कि नव उद्यमी प्रशिक्षण के साथ जागरूक करने के लिए 16 जुलाई को औद्योगिक क्षेत्र खलीलाबाद स्थित एसोसिएशन के कार्यालय प्रांगण में होना प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम के जरिए बेरोजगारों को उद्यम लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही साथ नया उद्यम लगाने वाले उद्यमियों को सरकार की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। बैंकों के प्रतिनिधियों के द्वारा समुचित सहयोग प्रदान कराया जाएगा। कार्यक्रम में जनपद स्तरीय संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। किसी भी उद्यमी को यदि उद्योग से संबंधित कोई समस्या होगी तो उसका निदान कराया जाएगा।

सीएम योगी ने बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात, अफसरों को निर्देश- पूरी तैयारी रखें, कोई भूखा न रहे

संवाददाता–श्रावस्ती। जिले में आई बाढ़ व कटान का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बृहस्पतिवार जमुनहा पहुंचे। जहां राप्ती बैराज स्थित गेस्ट हाउस में छह व सात जुलाई की रात रेस्क्यू कर बचाई गई रेखा देवी व फ्लड पीएसी के जवानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया साथ ही बाढ़ में डूबे चार परिवारों को राहत चेक व बाढ़ प्रभावितों को बाढ़ राहत किट प्रदान किया। इस दौरान मोटर बोट से नदी के दूसरे तरफ जाकर बाढ़ प्रभावितों से मिल कर उनका हाल भी जाना। जमुनहा गेस्ट हाउस पहुंचे मुख्यमंत्री ने छह व सात जुलाई की रात भरथापुर के निकट परवल के खेत की रखवाली करने गई किशोरियां व महिलाओं सहित 11 लोग राप्ती के बाढ़ में घिर गए थे। इस दौरान मोबाइल से प्रशासन से संपर्क कर सभी को सुरक्षित निकालने में सहयोग करने वाली रेखा देवी, पथ प्रदर्शक राम उजागर, फ्लड पीएसी के सोनू कुमार, अमरेश कुमार सरोज, शुभम सिंह, सतीश कुमार व मनोज कुमार को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही इन्हें बाद में अलग से सम्मानित करने व जिनके पास आवास नहीं है उन्हें आवास देने की बात कही।

इस दौरान बाढ़ के पानी में डूबे केवटन पुरवा निवासी लालजी पुत्र डेवा व चेतराम पुत्र फकीर तथा नौखान में डूबी सेहनिया निवासी शाहजहां पुत्री अकबर व जैनब उर्फ निबरी पुत्री मोहर अली के परिजनों को चार चार लाख रुपये का चेक प्रदान किया। इसके साथ ही शिकारी चौड़ा के बुद्धी, भोला, हरिहरपुर कानपुर पिपरहवा कोठी के छेदू व महंगू, वीरपुर लौकिहा के नादिर व जगदीश प्रसाद, जोगिया के राजेंद्र प्रसाद, रीता देवी, रामदयाल व शांति देवी सहित 100 बाढ़ पीड़ितों को राहत किट प्रदान किया।

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश में 33 तहसील, 633 गांव व 17 लाख 97 हजार आबादी बाढ़ की चपेट में आई है। जहां 18 हजार से अधिक पशु व एक लाख 45 हजार हेक्टेअर कृषि भूमि अचानक जलप्लावन के कारण प्रभावित हुई है। सभी गांवों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फ्लड पीएसी व स्थानीय स्तर पर नौकाओं की व्यवस्था की गई है। 1033 बाढ़ चौकी स्थापित कर वहां बाढ़ पीड़ितों को रखा जा रहा है। जिनके घर में पानी भर गया है। उन्हें रेस्क्यू करने की व्यवस्था की गई है। श्रावस्ती में 116 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। जहां पंद्रह गांवों में कटान हुई है। 76 हजार आबादी व 23500 हेक्टेअर कृषि भूमि प्रभावित है। बचाव राहत के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ व फ्लड पीएसी के साथ नाव आदि की व्यवस्था की गई है। जिले में चार जनहानि हुई है। पहले से व्यवस्था थी जो भी गांव व व्यक्ति बाढ़ की चपेट में आए हैं। उनके लिए राहत पैकेट की व्यवस्था है। सरकार ने आपदा राहत निधि से इसके लिए पहले ही व्यवस्था बना रखा है।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि इस बार भारी तैयारी होनी चाहिए ताकि कोई भूखा प्यासा न रहे। बाढ़ व कटान प्रभावित गांव में सर्पदंश व जानवरों के काटने की घटनाएं हो सकती है। इसके लिए सभी सीएचसी में एंटी स्नेक वेनम व एंटी रैबीज उपलब्ध कराने को कहा गया है। सरकार ऐसी स्थिति में तत्परता से कार्य कर रही है। हमने उन परिवारों से भी मुलाकात किया जो सात व आठ जुलाई की रात बाढ़ में फंस गए थे। इस दौरान जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्रा, श्रावस्ती विधायक रामफेरन पांडे, एमएलसी डा. प्रज्ञा त्रिपाठी, पदमसेन चौधरी, डीएम अजय कुमार द्विवेदी, एसपी घनश्याम चौरसिया सहित पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद रहा।

विधायक अजय सिंह ने बाढ़ पीड़ितों में किया राहत सामग्री का वितरण

संवाददाता–बस्ती। सरयू नदी की बाढ़ से घिरे दुबौलिया क्षेत्र के सुविकाबाबू और टेढ़वा गांव के 120 परिवारों को हरैया विधायक अजय सिंह ने गुरुवार को बाढ़ राहत सामग्री बांटी। विधायक ने तहसील प्रशासन के साथ बाढ़ पीड़ितों में लाई, आलू, आटा, तेल, माचिस, चावल, चना, पानी रखने का डिब्बा सहित अन्य रोजमर्रा की जरूरी सामानों का वितरण किया। विधायक अजय सिंह ने कहा कि प्राकृतिक आपदा रोकी नहीं जा सकती है बल्कि तत्परता दिखाकर हानि कम की जा सकती है हमारी सरकार ने प्रयास किया है कि सभी तक राहत सामग्री समय से पहुंचे। इसमें शासन प्रशासन के लोग लगे हुए हैं। हम लोग बाढ़ पीड़ित लोगों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहे हैं और कैंप स्थापित किया जा रहा है। सामग्री वितरण के दौरान तहसीलदार अभय राज, नायब तहसीलदार शौकत अली, ऋषभ सिंह, हल्का लेखपाल अशोक पटेल, अवधेश कुमार, ग्राम प्रधान श्री राम सिंह, अखिलेश सिंह, सुरेश सिंह, बब्बू सिंह, अजय सिंह, अखिलेंद्र सिंह, विशाल सिंह, राघवेन्द्र सिंह, गुलशन राजभर, अर्जुन पासवान, भारत सिंह, निर्मल सिंह, रंजन सिंह, दीपक, समीर चौहान आदि उपस्थित रहे।

ऑन लाइन हाजिरी, शिक्षक समस्याओं के निस्तारण के लिये मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

संवाददाता–बस्ती। गुरुवार को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष उदयशंकर शुक्ल के नेतृत्व में संघ पदाधिकारियों और शिक्षकों ने जिलाधिकारी द्वारा नामित उप जिलाधिकारी सदर को मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन भेजा। मांग किया कि ऑन लाइन डिजिटलाइजेशन के निर्णय को वापस लिये जाने के साथ ही शिक्षक समस्याओं का प्रभावी निस्तारण कराया जाय। संघ जिलाध्यक्ष उदयशंकर शुक्ल ने बताया कि ज्ञापन देने के पूर्व संघ के जिला और क्षेत्रीय कार्य समिति पदाधिकारियों की बैठक हुई जिसमें ऑन लाइन हाजिरी के साथ ही शिक्षकों के अन्य समस्याओं पर विचार किया गया। निर्णय लिया गया कि जब तक ऑन लाइन डिजिटलाइजेशन का निर्णय सरकार वापस नहीं लेती प्रदेश नेतृत्व के आवाहन पर चरणबद्ध ढंग से आन्दोलन जारी रहेगा। मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में कहा गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन विद्यालय की पंजीकाओं का डिजिटलाइजेशन व डिजिटल (डिजिटल फेस छायांकन) उपस्थिति कराए जाने संबंधी निर्देश को निरस्त किया जाय। इसी क्रम में परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक, शिक्षिकाओं को हॉफ सी०एल० की सुविधा दिये जाने, 30 ई०एल० की सुविधा देने, कैशलेस चिकित्सा सुविधा (बिना प्रीमियम) दियो जाने, परिषदीय शिक्षक, शिक्षिकाओं का ससमय स्थानानतंरण, पदोन्निति किये जाने, वेतन विसंगति समस्या का निराकरण करने, परिषदीय

विद्यालयों में लिपिक की नियुक्ति करने, परिषदीय विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति करने, परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक, शिक्षिकाओं को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किये जाने, शिक्षक, शिक्षिकाओं के जनपद स्तर की समस्याओं को निस्तारित किये जाने आदि की मांग शामिल है।

बैठक और ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से कार्यवाहक अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्र, वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेश कुमार, जिला मंत्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, जिला संयुक्त मंत्री विजय प्रकाश चौधरी, जिला कोषाध्यक्ष अभय सिंह यादव के साथ ही देवेन्द्र वर्मा, इन्द्रसेन मिश्र, रामभरत वर्मा, सन्तोष शुक्ल, रजनीश मिश्र, चन्द्रभान चौरसिया, दिवाकर सिंह, आनन्द सिंह, शशिकान्त धर द्विवेदी, सन्तोष शुक्ल, रवीश मिश्र, विवेककान्त पाण्डेय, ओम प्रकाश, अखिलेश चौधरी, कृष्ण कुमार उर्फ गुड्डू चौधरी, फैजान अहमद, चन्द्रशेखर शर्मा, गिरजेश चौधरी, रमेश चौधरी, पटेश्वरी निषाद, विनोद यादव, अनिल सिंह, धर्मेन्द्र उपाध्याय, शोमित श्रीवास्तव, अजय भारती, राजेश चौधरी, आशुतोष पाण्डेय, बब्बन पाण्डेय, रमेश विश्वकर्मा, चन्द्रशेखर पाण्डेय, अभिषेक जायसवाल, मारूफ खान, गिरिजाशंकर चौधरी, अश्विनी पाण्डेय, मुक्तिनाथ वर्मा, रामपराग चौधरी, लालता प्रसाद, राघवेन्द्र उपाध्याय, पवन कुमार मिश्र, दीपक सिंह, विजेन्द्र वर्मा, दीपक प्रेमी, सत्य प्रकाश मौर्य, रीता शुक्ला, सरिता पाण्डेय, रेखा वर्मा के साथ ही अनेक शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी एवं संगठनों के पदाधिकारी शामिल रहे।

पट्टा के लिए वसूली करने का आरोप

संवाददाता–गोण्डा। भूमि का पट्टा देने के लिए लाखों रूपयें की धनराशि लेने के बाद भी पट्टा न करने की शिकायत आयुक्त देवीपाटन मंडल से की गई है। मनकापुर तहसील के ग्राम शुक्लपुर की मुन्नी देवी पत्नी स्वर्गीय देवी प्रसाद का आरोप है कि लेखपाल ने अपने तैनाती के दौरान झूठ बोलकर कृषि पट्टा आवंटन करने के नाम पर छोटी छोटी किस्तों में एक लाख तिरसठ हजार रूपये ले लिए। विगत तीन वर्षो से सिर्फ कोरा आश्वासन देते रहे। उनका उस गांव से स्थानान्तरण भी हो गया। आरोप है रूपये मांगने गयी तो लेखपाल व उनके बेटे ने गाली देकर भगा दिया ,धमकी भी दी।

आनलाइन हाजिरी के विरोध में शिक्षकों ने बीएसए दफ्तर घेरा

संवाददाता–गोंडा। ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने गुरुवार को पंत नगर स्थित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया। शिक्षकों ने दोपहर दो बजे के बाद कार्यालय पर धरना – प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। इस दौरान शिक्षकों ने बीएसए अतुल कुमार तिवारी को मांग पत्र भी सौंपा। ऑलाइन हाजिरी का आदेश वापस होने तक शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन करते रहने की चेतावनी दी है। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष विनय तिवारी की अगुवाई में जिले के विभिन्न स्कूलों से आए शिक्षकों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। बीएसए कार्यालय परिसर में सुबह से शिक्षकों का समूह आना शुरू हो गया था। दस बजे परिसर में एक बड़ा सा पंडाल बनाया गया। इसमें शिक्षकों के बैठने के लिए कालीन और गद्दे बिछाए गए। दोपहर दो बजे तक सैंकड़ों की संख्या में शिक्षक इकट्ठा होकर डिजिटल पंजिका का विरोध करने लगे। शिक्षकों ने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन शिक्षकों की पूर्व में विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए संगठन ने अनेक पत्र दिए हैं। इसमें शिक्षकों के कैशलेश चिकित्सा सुविधा, पुरानी पेंशन बहाली, अंतर्जनपदीय और अंतः जनपदीय स्थानांतरण, पदोन्नति, विद्यालयों में ग और घ कर्मियों की नियुक्ति की मांग पहले से लंबित है। इसके विपरीत शिक्षकों पर दबाव डालने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद ने शिक्षकों को डिजिटल पंजिका रजिस्टर पर हाजिरी लगाने के निर्देश दे दिए। इससे शिक्षकों का निजता मूल अधिकार का हनन होता है। कहा कि दूसरी तरफ सचिवालय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा सहित विभिन्न विभागों में उपस्थिति की अन्य प्रणाली लागू की गई है। जिला अध्यक्ष विनय तिवारी ने कहा कि शिक्षकों की विभिन्न मांगों को न मानते हुए परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों पर ऑनलाइन हाजिरी का डिजिटलीकरण करना शिक्षकों के साथ दोहरा मापदंड है। जिला मंत्री उमा शंकर सिंह ने कहा कि परिषदीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों का डिजिटलीकरण करने से पहले अन्य मांगों का भी समाधान किया जाना चाहिए। धरने में विजय चौहान, आनंद देव सिंह, डॉ. अरुण सिंह, विपिन कुमार सिंह, रघुनाथ पांडे, डॉ. राजेश प्रताप सिंह, प्रतिभा सिंह, विश्वविजय नाथ पांडे, याकूब सिद्दीकी, गयालाल यादव, आनंद शुक्ला, भरत किशोर तिवारी, कन्हैया लाल मौर्या, देवकीनंदन शुक्ला, विनय सिंह, अवधेश मणी मिश्रा, अरुण कुमार शुक्ला, कुलदीप पाठक, बलवंत सिंह, राजेश कुमार शुक्ला, छाया सिंह, नरेंद्र कुमार सिंह, परसपुर विकास मंच के डॉ. अरुण सिंह सहित सैंकड़ों शिक्षक और शिक्षिकाएं शामिल हुए। जिले में एक तरफ शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी का विरोध जता रहे हैं तो वहीं 36 विद्यालयों में आनलाइन हाजिरी लगाने की खबर है। जिले में 2177 विद्यालयों के डिजिटलीकरण के लिए टैबलेट और सिमकार्ड का वितरण किया गया है। डीजी स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा के आदेश के बाद आठ जुलाई से ऑनलाइन हाजिरी लगाने के निर्देश में आठ जुलाई को 23 विद्यालयों और 9 जुलाई को 13 परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों ने डिजिटल पर काम किया है। डीसी ट्रेनिंग हरगोविंद ने बताया कि जिले में संचालित परिषदीय विद्यालयों में आठ को 23 विद्यालयों में और 9 जुलाई को 13 परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों ने शासन के निर्देश पर अपनी हाजिरी लगाकर 12 पंजिका रजिस्टरों पर काम पूरा किया है।

डाक पंजीकरण संख्या बी.एस.टी.62 R.N.I. 40367/84

साप्ताहिक
आवाज दर्पण
प्रत्येक रविवार

स्वत्वाधिकारी भारतीय बस्ती प्रकाशन की ओर से प्रकाशक एवं सम्पादक दिनेश चन्द्र पाण्डेय द्वारा 70 नया हाल जिला परिषद भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से प्रकाशित और मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस 70 नया हाल जिला परिषद भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित।
सम्पादक–दिनेश चन्द्र पाण्डेय
प्रबन्ध सम्पादक–दिलीप चन्द्र पाण्डेय

मो.०९४५०५६७४५०
Email- Awazdarpan@yahoo.com